● वर्ष-2
● अंक-233
रायपुर, रविवार
21 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

समाचार पचीसा के कार्यलय में 21 मई रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 23 मई मंगलवार को प्रकाशित होगा।

नरेन्द्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता

76 फीसदी लोगों ने कहा पीएम मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर बजा दुनियाभर में डंका। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दुनियाभर के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गये। रेटिंग फर्म द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री कुछ एक नहीं बल्कि 78 फीसदी लोगों की पहली पसंद बने हैं। दुनियाभर के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी दुनियाभर में इस लिस्ट में टॉप पर हैं।

यह सर्वे अमेरिका की कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने किया है और जारी रेटिंग 22-28 मार्च, 2023 के दौरान एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। फर्म के अनुसार करीब 76 फीसदी लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। फर्म का यह कहना है कि सिर्फ अमेरिका में इसके लिए 45,000 लोगों से बात की गई और वहीं इस रेटिंग सर्वे के लिए दुनियाभर में औसतन 500-5000 लोगों के बीच सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके बाद ही इस सर्वेक्षण के आधार पर यह लोकप्रियता रेटिंग निकाली गई। इस सभी सर्वेक्षणों में सिर्फ वयस्क लोगों को ही जोड़ा गया और इसे ऑनलाइन तरीके से कराया गया। साथ ही भारत में इस सर्वेक्षण के लिए खासतौर पर शिक्षित लोगों शामिल किया गया।सर्वे कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लोकप्रियता रेटिंग में 100 फीसदी लोगों में से 78 फीसदी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद माना है, वहीं 17 फीसदी लोगों ने उनके नाम को नामंजूर किया है और 4 फीसदी लोगों ने उनके बारे में कोई राय नहीं दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज़ ओब्रादोर हैं जिन्हें 61 प्रतिशत रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया केपीएम एंथनी अल्बनीज 55 फीसदी रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर रहे और साथ ही चौथे स्थान पर 49 फीसदी की अप्रूवल रेटिंग के साथ इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और पांचवे स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही लोकप्रियता के मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दसवें नंबर पर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ग्यारहवें स्थान पर रहे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ने इस सर्वे के लिए 22 वैश्विक नेताओं का सर्वेक्षण किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समेत विश्व के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने इस सर्वे में जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं को इसमें शामिल किया।

मोदी रोकेंगे रूस-यूक्रेन युद्ध!

जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में छात्र वहां फंसे हुए थे उनके लौटने को लेकर और वहां जो प्रयास किए गए थे उसकी तारीफ की। उसके साथ ही यूक्रेन के दर्द की चर्चा कर हर मुमकिन प्रयास का भरोसा भी दिया। इसके अलावा निजी तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि वो स्वयं भी अपने प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी की एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठे नजर आए। पीएम मोदी ने साफ कहा कि मैं इसे राजनीति और अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। मानवीय मूल्यों का मामला है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सब से ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया। उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना को भलि-भांति समझ पाता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं भी, हमसे जो कुछ भी हो सकता है वो हम अवश्य करेंगे। भारत लगातार शांति की बात करता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी यही बात दोहराई है।

जी-20 की बैठक से दूर रहेंगे पाकिस्तान के खास मित्र देश

नई दिल्ली। कश्मीर में जी-20 की बैठक की तैयारियां एक ओर अंतिम चरण में हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान के मित्र देश चीन ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा है कि वह कश्मीर में आयोजित हो रही जी-20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। हम आपको बता दें कि चीन ने इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जी-20 समूह की एक बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इस प्रकार की भी रिपोर्टें हैं कि ओआईसी सदस्य देश तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भी अभी तक बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। माना जा रहा है कि यह तीनों इस्लामिक देश बैठक से दूर रह सकते हैं। इस तरह देखा जाये तो पाकिस्तान भले जी-20 की बैठक को बाधित नहीं कर पाया लेकिन उसने इस्लामिक देशों और अपने मित्र देश चीन को कश्मीर में होने वाली बैठक में नहीं जाने के लिए मना लिया है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत का पूरा ध्यान अभी जी-20 बैठक को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने पर है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान की नापाक हरकतों का तगड़ा जवाब दिया जाता है उसी तरह जी-20 बैठक के विरोध में पाकिस्तान जो अभियान चला रहा है उसका भी माकूल जवाब सही समय पर दिया जायेगा।

चीन की प्रतिक्रिया

जहां तक चीन का सवाल है तो आपको बता दें कि उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा, ''चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की जी-20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है।'' उन्होंने कहा, ''हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे।'' हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन ने पूर्व में भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बारे में अवांछित टिप्पणियां की हैं लेकिन भारत हमेशा ऐसे बयानों को खारिज भी कर चुका है और तगड़ा पलटवार भी कर चुका है। जहां तक भारत-चीन के संबंधों की बात है तो दोनों देशों के बीच तीन साल से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध है। भारत ने कहा है कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी तब तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते।

श्रीनगर में तैयारियां

दूसरी ओर जी-20 बैठक की बात करें तो आपको बता दें कि श्रीनगर में हो रही यह बैठक जम्मू-कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। श्रीनगर में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय आयोजन से देश और दुनिया भर में सकारात्मक संदेश भी जाएगा। इसलिए यहां के होटल व्यवसायी, शिक्षाविद्, राजनीतिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद वह देश कश्मीर के बारे में अपने यात्रा परामर्श को वापस लेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवक बढ़ेगी तो कश्मीर पर्यटन को लाभ होगा। प्रभासाक्षी संवाददाता से बातचीत में जी-20 बैठक की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अपनी राय रखते हुए इस बैठक के आयोजन को कश्मीर के लिए एक बड़ा उपहार करार दिया।

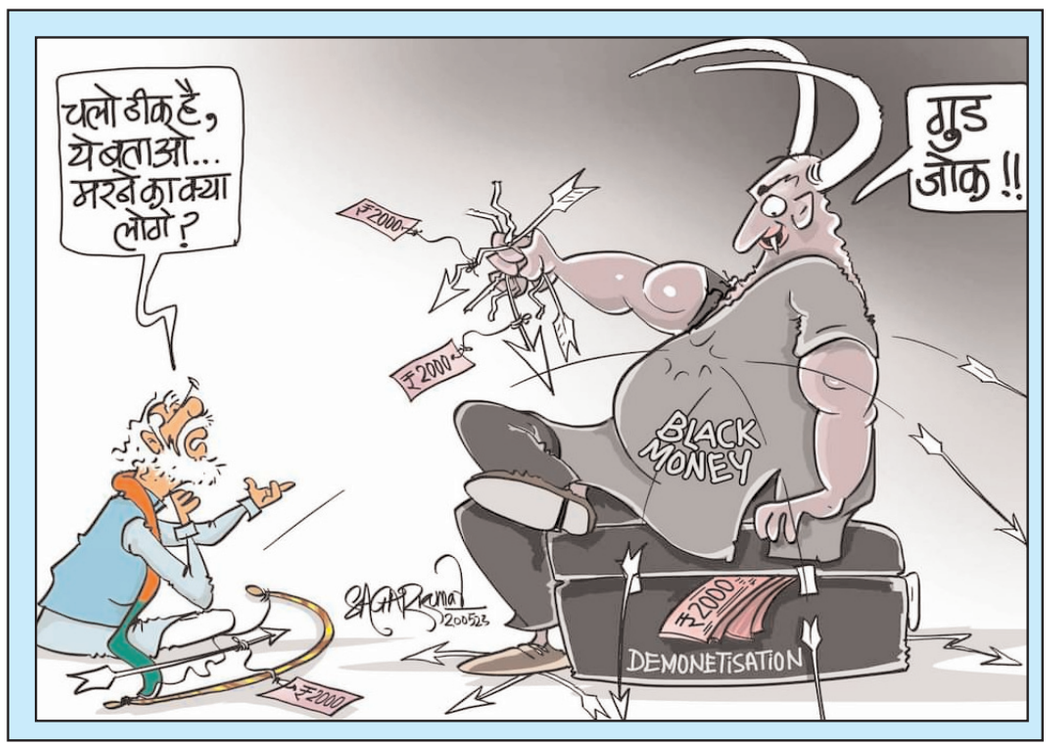

भारत ने फिर किया अमेरिकी धार्मिक रिपोर्ट का प्रतिकार

नई दिल्ली। अमेरिका ने फिर अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को अल्पसंख्यक विरोधी देश साबित करने की कोशिश की है। अमेरिका इसे विश्व भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक दस्तावेज बताता है। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कार्यालय के विशेष राजदूत राशद हुसैन ने कहा कि रिपोर्ट विश्व भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में एक तथ्य आधारित व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसे जारी करते हुए भारत का उल्लेख नहीं किया, पर रिपोर्ट में भारत का संदर्भ भयानक तस्वीरों से भरा है। राशद हुसैन के बयान में भारत का जिक्र है। उन्होंने कहा कि कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा है। चीन और अफगानिस्तान समेत कई देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विविध धार्मिक समुदाय से जुड़े कानून के हिमायती और धार्मिक नेताओं ने हरिद्वार में मुस्लिमों के खिलाफ घोर नफरती भाषा का इस्तेमाल किया, जो निंदनीय है।

इसमें 20 से अधिक ऐसी घटनाओं का जिक्र है, जिससे आभास होता है कि भारत की वर्तमान सरकार के अंदर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है। जैसे, कहा गया है कि इस वर्ष कई राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों के खिलाफ कानूनी एजेंसी के अधिकारियों द्वारा हिंसा की रिपोर्ट सामने आई। गुजरात में सादी वर्दी में पुलिस द्वारा अक्तूबर में एक त्योहार के दौरान हिंदुओं को घायल करने के आरोपी चार मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल में खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की बात कही गई है। इसे मुस्लिमों पर अत्याचार के रूप में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बुलडोजर से घर और संपत्तियां ध्वस्त करने का भी उल्लेख है। कोई निष्पक्ष और विवेकशील व्यक्ति इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकता।

अमेरिकी रिपोर्ट में भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका को नजर अंदाज किया गया है। इसमें तथ्यात्मक गलतियां भी हैं। उदाहरण के लिए, हरिद्वार की जिस सभा का जिक्र है, उसके कई लोगों पर न केवल मुकदमे हुए, बल्कि उन्हें जेलों में भी डाला गया। भारत को पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान आदि की श्रेणी में रखना साफ करता है कि रिपोर्ट तैयार करने वालों का उद्देश्य क्या हो सकता है। यह रिपोर्ट मीडिया एडवोकेसी रिसर्च ग्रुप्स द्वारा तैयार की गई है। इसमें कौन-कौन सी संस्थाएं और लोग शामिल हैं इनकी जानकारी सामने आनी चाहिए। राशद हुसैन पाकिस्तानी मूल के हैं।

प्रमुख समाचार

सिद्धारमैया कैबिनेट ने पांच गारंटी को मंजूरी दी

बेंगलुरू। कर्नाटक में आज सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं आठ अन्य विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस सरकार ने उन 5 गारंटियों को लेकर आदेश पारित किया है जिसको चुनावी मेनिफेस्टो में कहा गया था। सिद्धारमैया ने कहा हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कांग्रेस की पांच गारंटी को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि घोषणा पत्र में पांच गारंटियों का वादा किया गया था और उन पांचों गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट की पहली बैठक के बाद दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगली कैबिनेट बैठक के बाद सभी लागू होंगे जिसे एक सप्ताह के भीतर बुलाया जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा कि जो सरकारें पहले चलती थीं वे बेकार थीं, वे हमें करों का हिस्सा ठीक से नहीं दिला सके।

जो कांग्रेस छोड़ते हैं, सब उनका हाल जानते: रंधावा

नई दिल्ली। राजस्थान में कांग्रेस में जारी आंतरिक लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पायलट खेमे के साथ चल रही कलह हर दिन नए आरोप-प्रत्यारोपों के साथ आगे बढ़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच कांग्रेस के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने शनिवार को कहा कि पार्टी असंतुष्टों को निष्कासित नहीं करेगी। रंधावा ने कहा कि अतीत में नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद कैसा प्रदर्शन किया था, इसे भूलना नहीं चाहिए। पायलट ने गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और परीक्षा पेपर लीक पर कथित निष्क्रियता के लिए हमले की एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हाल ही में अजमेर से जयपुर तक पांच दिवसीय और 125 किलोमीटर की जन संघर्ष यात्रा आयोजित की और कहा कि यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और युवाओं के लिए है।

नौ घंटे से अधिक चली अभिषेक बनर्जी से पूछताछ

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी कुंतल घोष पत्र मामले में नौ घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय से बाहर आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ से जुड़े वीडियो और ऑडियो दिल्ली सीबीआई के उच्चाधिकारियों को भेज दी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार कुंतल घोष ने एक पत्र लिख कर आरोप लगाया था कि जांच एसेंजियां उस पर तृणमूल के बड़े नेताओं सहित महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दवाब बना रहे हैं। उससे ठीक एक दिन पहले कोलकाता में आयोजिक एक जनसभा में अभिषेक बनर्जी ने भी इसी तरह का की बात कही थी। उसके अगले दिन ही कुंतल ने वही आरोप लगाकर पत्र लिखा। अब सीबीआई अभिषेक बनर्जी से यह जानना चाहेगी कि उनको एक दिन पहले इस बारे में कैसे पता चला कि कुंतल घोष पर दबाव बनाया जा रहा है।

अब 30 गुना अधिक होंगे लू के थपेड़े, भारत में 55 डिग्री

नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। इन दिनों तापमान

40 से 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। देश में लू के थपेड़े 30 गुना अधिक होंगे। जिस तरह से कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और यह बढ़ता जा रहा है। इससे आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले वर्षों में राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों का औसत तापमान अभी की तुलना में 7 से 8 डिग्री और बढ़ सकता है। एनालिसिस के अनुसार, दुनियाभर के हीटवेव हॉटस्पॉट्स में शुमार होने वाले इस क्षेत्र की हाई वल्नरेबिलिटी ने मौसम के असर को बढ़ा दिया। अप्रैल के दौरान, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों ने तीव्र गर्मी की लहर का सामना किया, लाओस में 42 डिग्री सेल्सियस और थाईलैंड में 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया।

उस मिग-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर वायुसेना ने लगाई रोक

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसे का शिकार हो रहे मिग 21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगा दी है। मिग-21 बेड़े में शामिल होने के बाद से 400 से अधिक दुर्घटनाओं में शामिल रहा है। हाल ही में राजस्थान में मिग-21 विमान के क्रैश होने के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। मिग-21 लड़ाकू विमानों के पूरे बेड़े को रोक दिया गया है क्योंकि 8 मई की दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। लंबे समय तक मिग-21 भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करते थे। 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल किए जाने के बाद, भारतीय वायु सेना ने अपने समग्र युद्धक कौशल को बढ़ाने के लिए 700 से अधिक मिग-21 लड़ाकू विमानों की खरीद की। वर्तमान में आईएएफ के पास लगभग 50 विमानों के साथ तीन मिग -21 स्क्वाड्रन हैं। आईएएफ ने पिछले साल शेष मिग -21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को चरणबद्ध करने के लिए तीन साल की समयसीमा को अंतिम रूप दिया।

मोदी सरकार के अध्यादेश के बाद केजरीवाल नाममात्र के मुख्यमंत्री रह जाएंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को अधिकारों की लड़ाई का विजेता घोषित किए हुए अभी हफ्ता भर ही गुजरा था कि केंद्र की तरफ से बैक टू बैक दो दिनों में दो बड़े निर्णय ले लिए गए। पहले तो शुक्रवार की शाम केंद्र की तरफ से अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला ले लिया। फिर अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में 11 मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दिया। ऐसे में अब दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई अब आगे और भी जारी रहने वाली है।

क्या था मामला?

2015 में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया था कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सेवाओं पर नियंत्रण रखेंगे। दिल्ली सरकार ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसने 2017 में अधिसूचना को बरकरार रखा। अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया। 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में दिल्ली और केंद्र के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून को निर्धारित किया। फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में था। जबकि संविधान पीठ ने बड़े सवालों का फैसला किया, जबकि विशिष्ट मुद्दों को दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा तय किया जाना था। 2019 में दो न्यायाधीशों, (जो 2018 में 5-न्यायाधीशों की बड़ी बेंच का भी हिस्सा थे), जस्टिस अशोक भूषण और एके सीकरी ने सेवाओं के विशिष्ट मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया। खंडित फैसला तब तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ और अंततः पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास गया, जिसने अब अपना फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में है, इस अहम कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया गया। दिल्ली में सर्विसेज के अधिकार को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो तर्क रखा था, काफी हद तक कोर्ट उस पर राजी दिखा।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एक बड़ीलकीर भी खींची जिससे भविष्य में दिल्ली का बॉस कौन वाले सवाल पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थिति न पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवाल का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा।

आर्टिकल 239एए पर स्थिति साफ

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 239एए पर भी बहुत कुछ साफ कर दिया। अब तक दिल्ली सरकार और केंद्र अपने-अपने तरह से व्याख्या करते थे और मतभेद बरकरार रहता था। इसी आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकार है और दिल्ली केलिए एए विशेष रूप से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आर्टिकल 239एए में दिल्ली विधानसभा को कई अधिकार दिए गए हैं। लेकिन केंद्र के साथ शक्तियों के संतुलन की बात भी कही गई है।

केंद्र लेकर आ गई अध्यादेश

दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात जारी अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। दिल्ली के सीएम अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सदस्य होंगे। दिल्ली के गृह सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। अध्यादेश में यह साफ किया गया है कि अथॉरिटी में फैसले वहुमत के आधार पर होंगे। देर रात अध्यादेश जारी किया गया।

धीरे-धीरे भाजपा मुक्त हो रहा भारत : भूपेश

भरोसे का सम्मेलन का आयोजन आज सांकरा में

पाटन। पाटन विधानसभा के ग्राम सांकरा में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन 21 मई को किया जा रहा है। इस आयोजन में करीब एक लाख लोगों की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पाटन पहुंचकर पाटन के कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी को लेकर रणनीति बनाई। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को भरोसे के सम्मेलन के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याओं को भी खुले मंच से सुना और निराकरण का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली अन्याय करने वालों के साथ नहीं रहता। भाजपा कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा मुक्त भारत हो रहा है। हिमालय से लेकर समुद्र तट कर्नाटक तक कांग्रेस की सरकार है। दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा के साथ लोक सभा की तैयारी में जुटे हैं। किसानों को समय समय पर पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि छग की पहचान बन गई है

आदिवासी नृत्य का आयोजन गांव गांव में मानस गान गमन पथ का विकास कर रहे है। भाजपा के पास अब कुछ मुद्दा नहीं है। भाजपा ने जितने भी हितग्राहियों को साइकिल, राशन कार्ड, सिलाई मशीन सहित सामान बांटे हैं, उसमें पूरा कमीशन लिया है।

कांग्रेस सरकार में सभी हितग्राहियों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। भाजपा राम के नाम से वोट मांगते है। कांग्रेस सरकार राम वन गमन पथ का विकास कर रहा है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में उन्होंने बताया कि अब गोबर से बिजली बनाने की भी योजना सरकार बना रही है।हिमालय से लेकर समुद्र तट कर्नाटक तक का आयोजन कर रहे है। राम वन कांग्रेस की सरकार तैयारी बैठक लिया। उन्होंने सभी बता दें कि पाटन विकासखंड के ग्राम कार्यकर्ताओं से अपील की कार्यक्रम में शामिल हो।

कार्यक्रम को खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रभारी गिरीश देवागन, अपैक्स बैंक के डायरेक्टर अपेक्स बैंक राकेश ठाकुर कांग्रेस नेता रजत शर्मा, बलदाऊ भाले, केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू, ब्लॉक जिला पंचायत सदस्य मोनू साहू मंच पर नीरज सोनी, प्रशांत शुक्ला, आदित्य ब्लाक अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, नगर पंचायत पाटन के अध्यक्ष भूपेंद्र कस्यप किरण चंद्राकर , पुरुषोत्तम तिवारी लिलेश वर्मा, कैलाश देवांगन, राजेश ठाकुर, पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष संजय यदु खिलावन चंद्राकर, विनय पटेल, केदार कश्यप, पुरुषोत्तम कस्यप ,आयोग के उपाध्यक्ष आर एन वर्मा, हेमंत देवागन जयवर्मा, बल्लू राय, त्रिभुवन कश्यप, देवेश चंद्राकर, कमलेश वर्मा, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस अध्यक्ष संजय यदु छग साख सहकारी समिति सेक्टर 1भिलाई के अध्यक्ष जवाहर वर्मा,त्रिभुवन यदु, बबलू मारकंडे, सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र गायकवाड,शंकर बघेल, ब्लाक महिला अध्यक्ष जागेत्री साहू, राकेश आडिल वंदना वर्मा, त्रिवेणी बंजारे, मोरध्वज साहू, ईश्वरी वर्मा, योगेश्वर वर्मा, संदीप कश्यप जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक साह, सुरेंद्र गायकवाड, जनपद अध्यक्ष रामबाई रमन टिकरिहा, गालव वर्मा, छोटू बघेल दुर्गा कमलेश नेताम, सरपंच पुष्पा वर्मा, शशिकला भेष आठे, देव कुमार निषाद, मनीष पटेल थे। कार्यक्रम का संचालन कृषि मंडी दुर्ग के अध्यक्ष अश्वनी साहू व आभार जिलाध्यक्ष निर्मल कोसरे ने किया।

अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक

आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। विधानसभा चुनाव को अभी छह महीने शेष हैं चुनाव की तारीख की भी कोई घोषणा नहीं हुई है। मरवाही के विधायक डॉ. केके ध्रुव को अगला कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर उनकी ही पार्टी के आदिवासी कांग्रेसी नेता सहित सर्व आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि विरोध करने लगे हैं। उनको बाहरी आदिवासी व्यक्ति बताते हुए अपनी ओर से दूसरा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर लामबंद हो गए। जबकि इन सब खींचतान से अलग विधायक केके ध्रुव इलाके में जनसंपर्क में लगे हुए हैं।

आदिवासी सीट मरवाही विधानसभा में चुनाव के पूर्व ही आदिवासी विधायक केके ध्रुव का विरोध आदिवासियों ने ही शुरू कर दिया है। सर्व आदिवासी समाज ने पूर्व विधायक पहलवान सिंह मरावी की अध्यक्षता में मीटिंग करते हुए सभी आदिवासी समाज के प्रमुख विधायक केके ध्रुव के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। और आदिवासी समाज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आदिवासी नेताओं का कहना है कि हमें कांग्रेस पार्टी स्थानीय प्रत्याशी दे, वह किसी भी आदिवासी वर्ग का हो सकता है। हमें केके ध्रुव स्वीकार नहीं क्योंकि केके ध्रुव बाहर के हैं, इसलिए वह स्थानीय आदिवासियों के हितों को ध्यान नहीं दे रहे हैं।

सांसद ज्योत्सना महंत की पहल : रियाज व बग्गा को मिली चिकित्सा सहायता

- 2 वर्ष के मासूम मनतेक सिंह और 13 वर्षीय अर्शिल के ईलाज में होगी मदद

कोरबा। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के द्वारा संसदीय क्षेत्रवासियों के सुख.दु:ख में एक कदम आगे बढक़र कार्य और सहयोग किया जाता रहा है। इस कड़ी में उन्होंने संज्ञान में लाए जाने पर 2 बच्चों के गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र व्यवहार कर प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद के लिए पहल किया। सांसद की संवेदनशील पहल के फलस्वरूप बड़ी राहत राशि प्राप्त हुई है।

कोरबा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 11 नई बस्ती मेन रोड कोरबा निवासी मो. रियाज मेमन के 13 वर्षीय पुत्र मो.अर्शिल मेमन को थैलिसीनिया मेजर नामक गंभीर रोग है। रियाज मेमन ने पुत्र के उपचार हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत के समक्ष आग्रह किया। सांसद ने उक्त संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित पत्र लिखकर प्रधानमंत्री राहत कोष से अपेक्षित आर्थिक मदद के लिए आग्रह किया।

इसी तरह महाराणा प्रताप नगर कोरबा के ईडब्यूएस निवासी सन्नी बग्गा का पुत्र मनतेक सिंह बग्गा 2 वर्ष बोन मेरो ;रीढ़ की हड्डी रोग से पीड़ित है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के

कारण परिवार उपचार करा सकने में असमर्थ है। सांसद ने उक्त परिवार के लिए भी आर्थिक मदद हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र प्रेषित किया। इन दोनों ही पत्रों पर संज्ञान लेते हुए 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तत्संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के अवर सचिव ;वित्त प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत को 3-3 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से स्वीकृत किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। उक्त स्वीकृति के संबंध में नारायणा हृदयालय बैंगलोर कर्नाटक के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी अवगत कराया गया है ताकि रोगी के उपचार में किसी तरह की बाधा न हो।

सांसद का जताया आभार:-बच्चों के उपचार हेतु आवश्यक आर्थिक सहायता राशि प्रदाय कराने हेतु आवश्यक गंभीर पहल किए जाने व स्वीकृति मिलने पर मो. रियाज मेमन व सन्नी बग्गा सहित उनके परिजनों ने सांसद ज्योत्सना महंत के प्रति आभार व्यक्त किया है।

कोरबा में भाजपा पार्षद के क्षेत्र में जबरिया दखल देने का आरोप

कोरबा। कोरबा के वार्ड क्रमांक 5 में बनाए गए सियान सदन में दूसरे वार्ड के पार्षद को महत्व देने का आरोप लगाते हुए लेकर भाजपा पार्षद दल आक्रामक मूड में आ गया है। उक्त व्यवस्था को अनुचित बताते हुए अपर आयुक्त से मिलकर विरोध जताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर व्यवस्था को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भाजपा पार्षद अपने वार्ड में अपने हिसाब से काम करेंगेए साथ ही सियान सदन के तीन रंग पर भी भाजपा ने आपत्ति जताई है।

नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने सियान सदन में स्थानीय पार्षद की उपेक्षा और कांग्रेसी रंग में रंगने का आरोप लगाकर इस प्रयास को गैरजरूरी और अवैधनिक बताया। अपर आयुक्त खजांची कुम्हार से मिलकर भाजपा पार्षदों ने साफ्तौर पर कहा कि इसे तत्काल ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नही किया जाता है भविष्य में सभी भाजपा पार्षद अपने वार्ड में विकास कार्य अपने तरीके से करेंगे।

वार्ड पार्षद धनश्री साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिक निगम के द्वारा अधोसंरचना मद से धनवारपारा वार्ड संख्या 5 में सियान सदन बनाया है। इस काम पर लाखों रुपए खर्च किए गए। इसके विपरीत भवन में इस वार्ड के पार्षद भाजपा की धनश्री साहू के बजाय वार्ड 6 के कांग्रेस पार्षद का नाम अंकित कर दिया गया है। यह आपत्तिजनक है। इस दौरान पार्षद सुश्री चौरसिया, सुफल दास महंत, नरेंद्र देवांगन, नारायण दास महंत, निखिल शर्मा, कमला बरेठ सहित भाजपा पार्षद उपस्थित थे।

अस्तित्व विहीन हो चुका धमधा का 'हाथी बुढ़ान' तालाब हुआ पुनर्जीवित

- 12 शासकीय तालाबों से अतिक्रमण हटाकर, प्रशासन व जनभागीदारी से किया जा रहा है गहरीकरण व जीर्णोद्धार

दुर्ग। विगत कई महीनों के निरंतर प्रयास से जिला प्रशासन को दुर्ग के विकासखंड धमधा में एक बहुत बड़ी सफलता जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त हुई है। 40 वर्ष पूर्व अस्तित्व विहीन हो चुके धमधा के छह तालाबों को पहले खोजा गया, फिर कब्जा हटाया गया और फिर उसकी खुदाई कर तालाब को उसका मूल स्वरूप दिया गया। इन तालाबों को राजस्व विभाग ने स्थानीय जनों के सहयोग व अपने अथक प्रयास से पुर्नजीवित किया।

ये तालाब इतिहास के पन्नों में तो अंकित थे लेकिन वर्तमान में अपना मूल स्वरूप खो चुके थे। कुछ स्थानीय किसानों के द्वारा इसे पूर्णता पाट कर खेत का स्वरूप दे दिया गया था। इन विलुप्त तालाबों की बहाली के लिए जिला प्रशासन, योजनाबद्ध तरीके से सक्रिय कार्य कर रहा था। जिसके अंतर्गत उसने जनसहयोग के माध्यम से पुराने तालाबों का चिन्हांकन किया। 1909, 1921-22, 1929-30, 1984-85 राजस्व लैण्ड रिकार्ड से मिलान कर, 12 नेस्तनाबूद

विलुप्त तालाबों का चिन्हांकन किया और इनका सीमांकन किया। जिनका जनभागीदारी के माध्यम से सतत् जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हाथी बुढ़ान, घोड़ा बुढ़ान, बनफरा का तालाब व बनफरा का पैठू प्राचीन तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और तेली डबरी व लोकईया तालाब की खुदाई का कार्य चल रहा है।

6 कोरी 6 आगर तालाब वाला धमधा फिर बनेगी तालाबों की नगरी-धमधा के तालाबों के संकलन पर आधारित गोविंद पटेल द्वारा लिखित पुस्तक ''छै कोरी, छै आगर तरिया अऊ बूढ़ा नरवा'' के विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष धर्मधाम गौरवगाथा समिति के सदस्यों द्वारा विलुप्त हो चुके तालाबों के सीमांकन के लिए मांग की गई थी। जिस पर सकारात्मक पहल करते हुए 6 कोरी 6 आगर तालाब वाले पुरातात्विक नगर धमधा के गौरवशाली वैभव की पुर्नस्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ समय पूर्व जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए थे। जिसका अमल करते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में धमधा के एसडीएम बृजेश सिंह क्षत्रिय ने विलुप्त हो चुके तालाबों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना प्रारंभ किया।क्योंकि यह कार्य जटिल था इसलिए प्रशासन ने खेत की जानकारी रखने वाले स्थानीय लोगों की सहायता ली। जिसमें गांव के बुजुर्ग और तरिया के क्षेत्र में संरक्षण कार्य करने वाले धर्मधाम गौरवगाथा समिति शामिल हुआ। समिति 3 साल पूर्व से ही इस दिशा में कार्य कर रही थी। जिसके अंतर्गत उसने प्रशासन को तालाबों के नाम, उनके निर्माणकर्ताओं की जानकारी, खसरा व रकबा नंबर इत्यादि उपलब्ध कराई। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 100 साल पुराने नक्शे व अन्य लैंड रिकॉर्ड से उपलब्ध जानकारियों का मिलान किया। इसके साथ ही पटवारियों की टीम के साथ मौके का मुआयना किया गया। विषय पर जानकारी देते हुए एसडीएम धमधा द्वारा बताया गया कि शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 26 तालाब अपने स्थान से विलुप्त हो चुके थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

स्वच्छता दीदियों ने नपा दीपका का किया घेराव

कोरबा। कोरबा-पश्चिम क्षेत्र में डोर.टू.डोर कचरा कलेक्शन करने वाले स्वच्छता दीदियों ने नगर पालिका दीपका का घेराव कर दिया। उन्होंने अध्यक्ष पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि काम करने वालो को परेशान किया जा रहा है जबकि बिना काम के भी 4 लोगो को मानदेय दिया जा रहा है। दीपका नगर पालिका परिषद में उस समय हड़कंप मच गया जब स्वच्छता दीदियों ने कार्यालय का घेराव कर अध्यक्ष की मनमानी नही चलेगी का नारा लगाने लगे! नगर के कचरा को इकट्ठा कर उसका निष्पादन करने वाली महिलाओं की भीड़ को देखकर पालिका के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने अध्यक्ष पर आरोप लगते हुए कहा कि हमे हमेशा अपमानित किया जा रहा है और अधिकारियों की बात न मानने पर हमारा निष्ठा एप को बंद कर दिया जाता है। जिससे हमारी ऑनलाइन हाजिरी नही लग पाती। पालिका के कर्मचारियों को इसकी शिकायत करने पर काम से निकालने की धमकी दी जाती है। स्वच्छता दीदी ने कहा कि मेरा निष्ठा एप बंद कर दिया गया है।

क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एक दिवसीय प्रवास पर रहे

राजनाँदगाँव। राष्ट्रिय स्वयं सेवक के अनुसांगिक संगठन क्रीड़ा भारती के राष्ट्रिय संगठन मंत्री प्रसाद महानकर 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के प्रथम दिवस पर राजनाँदगाँव प्रवास पर रहे। जहां उन्होंने जिले के विभिन्न खेलो से जुड़े पदाधिकारियो एवं खिलाड़ियों से परिचय किया एवं जानकारी ली। सर्वप्रथम उन्होंने मुसरा, डोंगरगढ़ स्थित क्रीड़ा केंद्र में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया एवं बैठक ली। तत्पश्चात कॉरिनभाठा राजनाँदगाँव स्थित सतनाम भवन में सभी खिलाड़ियों से चर्चा एवं कर आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं जिले में खेल के माहौल को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। अंत में ममता नगर में आयोजित बैठक में विभिन्न खेल संघ के पधादिकारियो के साथ बैठक कर परिचय प्राप्त किया एवं खेलो में कैसे ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाय इसपर चर्चा किया एवं महत्वपूर्ण जानकरी साझा की। इस अवसर पे मुख्य रूप से क्रीड़ा भारती के राष्ट्रिय संघठन मंत्री प्रसाद महानकर, प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, सुमित उपाध्याय आदि उपस्थित थे।

रिसाली निगम मे नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ

रिसाली। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर पॉलिक निगम रिसाली में भाजपा पार्षद दल के नेता (नेता प्रतिपक्ष) का चयन अभी तक नही हो पाया है। जिसको लेकर पार्षदो में निराशा छा गया है। ज्ञात हो कि रिसाली पालिका में काँग्रेस के पार्षदो की संख्या अधिक है।लेकिन सदन में बैठक के दौरान विभिन्न मामलों को लेकर भाजपा के पार्षद जोर शोर से उठाते है। जिससे कई मामले उभर कर सामने आए है। लेकिन भाजपा संगठन नेता प्रतिपक्ष बनाने में देरी क्यो कर रही है। जिसको लेकर अब तरह के प्रश्नन भी उठने लगें है।सूत्र बताते है कि रिसाली निगम में नेता हेतु रमा साहू, पार्षद विधि यादव, धर्मेंद्र भगत, मनीष यादव, माया यादव के नामों की चर्चा है। अब चूंकि रिसाली मण्डल में मण्डल अध्यक्ष, महिला व युवा मोर्चा अध्यक्ष में नियुक्तिया हो गई है। फिर ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष का चयन न होना समझ से परे है।

भाजपा मध्य मंडल महिला मोर्चा की बैठक सम्पन्न

पाटन। भारतीय जनता पार्टी मध्य मंडल पाटन के महिला मोर्चा की बैठक पाटन में आयोजित की गई। जिसमें सरकार के जनविरोधी कार्यो का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक को जिला भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती दिव्या कलिहारी ,मध्य मंडल पाटन के अध्यक्ष खेमलाल साहू ,उत्तर मंडल अध्यक्ष लोकमनी चंद्राकर व हरिशंकर साहू ने भी सम्बोधित किया। संचालन रानी बन्छोर एवं आभार सीता देवांगन ने किया। बैठक मे प्रमुख रूप से जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष दिव्या कलिहारी,जिला पंचायत सदस्य हर्षा चंद्राकर, जिला महामंत्रीद्वय गायत्री वर्मा एवं जयराजपूत, मंजुलता अंगारे, योगिता शर्मा, मध्य मंडल अध्यक्ष खेमलाल साहू, उत्तर मंडल अध्यक्ष लोकमनी चंद्राकर, हरिशंकर साहू, होरीलाल देवांगन, केशव बन्छोर, यमन मड़रिया,लक्ष्मण साहू, रानी बन्छोर, पार्षद चंद्रकला, सीता देवांगन ,तनुजा साहू, ललिता साहू,संध्या साहू, प्रीति वैष्णव, प्रियंका वर्मा उपस्थित थी।

झांसा देकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से धोखाधड़ी

रिसाली। स्वयं को ट्रासपोर्ट का कार्य करना और आर्डर के लिए भिलाई एवं रायपुर में सप्लाई के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाकर लाखों रुपए एडवास लेकर धोखाधड़ी की है। रिपोर्ट पर पुलिस मामले में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।नेवई पुलिस ने बताया कि मैत्रीकुंज रिसाली निवासी अनुराग कुमार रॉय (45 वर्ष) ट्रान्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे छोटी गाड़ी 10 टन से 45 टन तक की गाडियां किराये पर लगाने का कार्य करते हैं और ब्लैक बक के ट्रान्सपोर्ट एप्स में जुड़े हैं। इसमें सुनील कुमार का लोहे का मटेरियल बाम्बे से भिलाई एवं रायपुर लाने के लिये काम लिया था। करीब 400 टन माल बाम्बे से लाना था । प्रार्थी को 22 सितंबर 2022 में किसी कुलदीप नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिन्होने बताया कि वह ट्रान्पोर्ट का कार्य करता है। उसने बताया कि उसके पास गाड़ी उपलब्ध है। प्रति टन 2600 रू किराया भाड़ा तय हुआ एडवांस के रूप में उसने 1,10,000 रू की मांग की।

विभिन्न कार्यों के लिए मेयर इन काउंसिल ने दी स्वीकृति

- महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई एमआईसी की बैठक

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित एम.आई.सी. कक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। नगर पालिक निगम कोरबा की मेयर इन काउंसिल द्वारा आज निगम के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यो, साफ-सफाई व्यवस्था, सड़क रोशनी व्यवस्था सहित विभिन्न सेवाओं व सुविधाओं से जुड़े कार्यो पर निर्णय लेते हुए विभिन्न कार्यो से संबंधित वार्षिक दर निर्धारित संबंधी प्रस्तावों पर भी मेयर इन काउंसिल द्वारा चर्चा हुई।

एम.आई.सी. द्वारा निगम के विभिन्न वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक, जे.सी.बी.आपरेटर, श्रमिक वाहन एवं निगम के विभिन्न वार्डो में विद्युत संधारण हेतु इलेक्ट्रीशियन प्रदान करने, नगर पालिक निगम कोरबा के समस्त जोन के विभिन्न वार्डो में डामरीकृत सड़कों का मरम्मत एवं पैच रिपेरिंग

कार्य, जल आवर्धन योजना भाग-1 का संचालन व संधारण कार्य, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर स्थित स्वीमिंग पूल के संचालन कार्य के संबंध में तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार अधोसंरचना मद, वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित कार्यो के संबंध में एम.आई.सी.द्वारा आवश्यक निर्णय लिया गया।

इसी के साथ महापौर ने प्रगतिरत कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि विशेष रूप से आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नाली-नालों की पूर्णतया सफाई एवं डामरीकरण के कार्य में तीव्रता लायी जावे एवं इसके साथ-साथ अन्य सभी निर्माणाधीन संरचनाओं के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जावे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत किये जाने वाले महापौर निधि, पार्षद निधि एवं एल्डरमेन निधि के तहत विकास कार्यो के प्रस्ताव मंगाकर उसका प्राक्कलन तैयार कर अतिशीघ्र निविदा जारी करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए गए।

बैठक के दौरान मेयर इन काउंसिल सदस्य संतोष राठौर, सुनील पटेल, कृपाराम साहू, सुनीता राठौर, मस्तुल सिंह कंवर, प्रदीप जायसवाल, पालूराम साहू, सपना चौहान, रोपा तिर्की, सुख सागर निर्मलकर, फूलचंद सोनवानी, सुरती कुलदीप, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, अधीक्षण अभियंता एम.के.वर्मा, उपायुक्त पवन वर्मा, बी.पी.त्रिवेदी, कार्यपालन अभियंता ए.के.शर्मा, एम.एन.सरकार, आर.के.माहेश्वरी, तपनयोगी तिवारी, अखिलेश शुक्ला, भूषण उरांव, विनोद शांडिल्य, एन.के.नाथ, प्रकाश चन्द्रा, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर आदि उपस्थित थे।

आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन, सीजीपीएससी में अनियमितता की शिकायत व जांच की मांग

कोरबा। आम आदमी पार्टी कोरबा इकाई के तत्वाधान में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सौंपा गया। पदाधिकारियों ने अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बीते दिनों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 का परिणाम जारी हुआ है। जिसकी विश्वसनीयता व पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं स इस मामले को लेकर सीजी पीएससी की कोचिंग कर रहे अभ्यर्थी की एक चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है स चिट्ठी में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैंए जिससे लोक सेवा आयोग पर

प्रश्नचिन्ह लग रहा है स ऐसे में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग कर रही है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, नहीं तो युवा वर्ग का राज्य प्रशासनिक सेवा आयोग से विश्वास उठ जाएगा स युवाओं के मेहनत पर पानी फिर जाएगा।

जिला अध्यक्ष चंद्रकांत डिक्सेना ने चेतावनी दी है किए यदि इस पर सुनवाई नहीं की जाती तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। जिला जिला सचिव गौरव यादव ने बताया कि परिणाम में धांधली हुई है और आप पात्रों का चयन कर लिया गया है जो की मेहनती युवाओं के साथ छल है। इस मौके पर जिला कोषाध्यक्ष आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अमर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी शत्रुघ्न साहू, प्यारे लाल चौहान, प्रकाश दास, सपन बहादुर, पार्टी की ओर से एवं आकाश राखोंडे, प्यारे लाल चौहान और बमलेश यादव पीएससी अभ्यर्थियों का प्रतिनधित्व करते हुए उपस्थित थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अफसरों की ट्रांसफर- पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने के 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर- पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात जारी अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। दिल्ली के सीएम अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया।

केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है : केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश 'असंवैधानिक' है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना, जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने 'दानिक्स' काडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने थामा बीजेपी का दामन

जयपुर। राजस्थान में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। इस खबर के सामने आने के बाद निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है। भाजपा में शामिल होने वाले अकेले सुभाष महरिया ही नहीं अन्य लोग भी है। इनमें सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रामदेव सिंह खारीवा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीआर मीणा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी गोपाल मीणा, नरसी किराड और हेमंत शर्मा भी शामिल है जिन्होंने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने से पहले महरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

केंद्र के एजेंसी-राज ने हमारा काम चुनौतीपूर्ण बना दिया है

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है केंद्र के 'एजेंसी-राज' ने राज्य का शासन चलाने के उनके काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्होंने वाम सरकार को हटाकर 2011 में पहली बार राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की वर्षगांठ के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। ममता ने ट्वीट किया, ''केंद्र में एक निरंकुश सरकार के एजेंसी-राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देशभर में लाखों लोग हमारे साथ हैं।'' उन्होंने कहा, ''वर्ष 2011 में आज ही के दिन हम 34 साल तक शासन करने वाली सरकार को हटाकर सत्ता में आए थे और पश्चिम बंगाल में 'मां, माटी, मानुष' सरकार बनायी थी।' ममता के ट्वीट से एक घंटे पहले तृणमूल कांग्रेस नेता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी निजाम पैलेस में सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए।

टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की नई चार्जशीट

नईदिल्ली। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पुल बंगश गुरुद्वारा आग मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ ताजा सबूत मिलने के बाद आरोपपत्र में उनका नाम लिया गया है। जांच एजेंसी ने पिछले महीने 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के संबंध में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने एकत्र किए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे। कांग्रेस नेता पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, हम गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन करने के लिए सहायक सबूत खोजने में कामयाब रहे हैं। टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आईपीसी की धारा 147, 148,149,153 (ए), 188 और 109 के साथ 302, 295 और 436 के तहत दायर की गई है।

समुद्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर बोले प्रधानमंत्री

संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : मोदी

हिरोशिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा में पहुंचे हैं। इस दौरान, उन्होंने जापान के प्रमुख अखबार योमिउरी शिंबुन से कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात की। इसमें उन्होंने जी-7 और जी-20 के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने चीन की सैन्य गतिविधियों से निपटने पर भी बात की।

पीएम मोदी ने विकासशील और उभरते देशों समेत ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को हल करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, आर्थिक सुधार, ऊर्जा अस्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा और शांति और सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जी-7 और जी-20 के बीच सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

वहीं, उनसे जब पूछा गया कि भारत दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के सैन्य विस्तार, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ताइवान जलसंधि में बढ़ते तनाव से कैसे निपटेगा? तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत संप्रभुता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का सम्मान करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर हम समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देते हुए अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के साथ भूमि और समुद्री सीमाओं को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

इस मौके पर पीएम मोदी ने यूक्रेन मामले पर भी बात। यूक्रेन पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतराष्ट्रीय कानून के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। हम संयुक्त राष्ट्र और उसके बाहर रचनात्मक योगदान देने के लिए तैयार है।

ग्लोबल साउथ के प्रमुख नेता के रूप में पीएम मोदी ने आपूर्ति में बाधा, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को दूर करने की प्राथमिकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य विभिन्न आवाजों के बीच एक पुल के रूप में काम करना है। दुनिया को कोविड-19 महामारी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विकासशील देशों को प्रभावित कर रही है। भारत इन चिंताओं को दूर करने को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि जापान और अन्य भागीदारों के सहयोग से हम मानव-केंद्रित विकास पर जोर देते हैं। भारत मानवता की भलाई के लिए साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रचनात्मक एजेंडे को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक से भी मुलाकात की

जापान के हिरोशिमा शहर में जी-7 शिखर सम्मेलन में शनिवार को पीएम मोदी ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मेहमान देश के तौर पर पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने दुनियाभर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तक शामिल रहे। पीएम मोदी ने इस बैठक में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। यहां भी दोनों नेताओं ने गले लगाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। ब्रिटेन पीएम सुनक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गले मिलने की तस्वीरें भी शेयर की है। पीएम मोदी जी-7 सम्मेलन के लिए जापान में 19 से 21 मई तक रहेंगे, इसके बाद वह एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पापुआ न्यू गिनी जाएंगे।

एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिले मोदी और बाइडेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 की बैठक में शामिल होने के लिए जापान के हिरोशिमा में हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर मोदी जापान पहुंचे हैं। हालांकि, जी7 की बैठक के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो बाइडेन खुद उनके पास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक बातचीत भी की। इस दौरान दोनों नेता काफी खुश दिख रहे हैं। दोनों हाथ मिलाते हुए मुस्कुराते भी नजर आ रहे हैं। मोदी-बाइडेन की इस मिलन से दोनों देशों के बीच रिश्तो की नई तस्वीर सामने आई है। जापान के हिरोशिमा में जी7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने स्वागत किया। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में प्रसिद्ध जापानी लेखक, हिंदी और पंजाबी भाषाविद्, पद्म श्री डॉ. तोमियो मिजोकामी और प्रमुख जापानी चित्रकार हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। मोदी ने इसको लेकर कहा कि हिरोशिमा में मुझे प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी के साथ बातचीत करके खुशी हुई। पद्म पुरस्कार विजेता, वे एक प्रतिष्ठित हिंदी और पंजाबी भाषाविद् हैं। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैंने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली सम्मानित कलाकार हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। उन्होंने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है।

सिद्धारमैया ने ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ

डीके शिवकुमार बने डिप्टी सीएम, विपक्षी एकता की दिखी झलक

बेंगलुरु। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं वहीं डीके पहली बार डिप्टी सीएम बने हैं। बेंगलुरु के कांतीरवा स्टेडियम में गांधी परिवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और विपक्ष के बड़े नेताओं की मौजूदगी में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

सिद्धारमैया और डीके के साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जी परमेश्वर, लिंगायत नेता और पांच बार के विधायक एम बी पाटिल और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे, के एच मुनियप्पा, के जे जॉर्ज, सतीश जार्कीहोली, रामालिंगा रेड्डी और बी जेड जमीर अहमद खान ने मंत्री पद की शपथ ली।

एच मुनियप्प देवनहल्ली से विधायक हैं। वे 2009 में रेल राज्यमंत्री रहे। मुनियप्पा दलित समुदाय से आते हैं। वहीं के जे जॉर्ज- सर्वज्ञनगर से छठी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। बंगारप्पा सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। जॉर्ज का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से है। जार्कीहोली अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं, जबकि रामालिंगा रेड्डी का संबंध रेड्डी जाति से है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उप मुख्यमंत्री शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के हैं।

बेंगलुरु में हुए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार शामिल हुए। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, मक्कल नीडि माईम के प्रमुख कमल हसन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री

भूपेश बघेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मंच पर मौजूद थे।

सिद्धारमैया के सामने पहली चुनौती सही संतुलन के साथ मंत्रिमंडल के गठन की है, जिसमें सभी समुदायों, धर्म, वर्गों और पुरानी तथा नयी पीढ़ियों के विधायकों का प्रतिनिधित्व हो। कर्नाटक मंत्रिमंडल में मंत्रियों की स्वीकृत संख्या 34 है और अनेक विधायक मंत्री पद की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धारमैया के शपथ के बाद बोले राहुल- कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती

सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने के लिए जनता का धन्यवाद किया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर भी जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की नफरत को हरा दिया और यहां के लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते। हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में जो 5 गारंटी दिए हैं, उसको हर हाल में लागू करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे।

खेल
प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स लगातार नौवें सीजन में लीग राउंड से बाहर

धर्मशाला। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को आईपीएल से बाहर कर दिया। राजस्थान ने इस मैच में चार विकेट से जीत हासिल की। उसने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। दूसरी ओर, पंजाब की टीम लगातार नौवें सीजन में लीग राउंड में ही बाहर हो गई। वह पिछली बार 2014 में प्लेऑफ तक पहुंची थी। तब वह उपविजेता रही थी। आईपीएल के 16 सीजन में पंजाब सिर्फ दो बार ही लीग राउंड से आगे बढ़ पाया। 2009 में वह सेमीफाइनल तक पहुंचा था। राजस्थान को जीत के लिए आखिरी ओवर में नौ रन की आवश्यकता थी। ध्रुव जुरेल और ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआती तीन गेंद पर चार रन बना लिए। इसके बाद चौथी गेंद पर जुरेल ने छक्का लगाकर मैच को समाप्त कर दिया।

राजस्थान के लिए क्या हैं समीकरण?

इस जीत के बाद राजस्थान के 14 मैच में 14 हो गए। उसका नेट रनरेट +0.148 हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और मुंबई इंडियंस के भी 14-14 अंक हैं। मुंबई का नेट रनरेट (-128) में राजस्थान से कम है और वह छठे स्थान पर है। संजू सैमसन की टीम इस जीत के बाद पांचवें नंबर पर पहुंच गई। राजस्थान की टीम अगर इस मैच को 18.3 ओवर में जीत लेती तो उसका नेट रनरेट आरसीबी (0.180) से बेहतर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजस्थान की टीम इस बात की दुआ करेगी कि आरसीबी अपने अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बड़े अंतर से हारे। इसके अलावा मुंबई को भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त मिले। पंजाब की बात करें तो 14 मैच में 12 अंक के साथ वह आठवें स्थान पर है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

2000 का नोट वापस लेने से अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा : पनगड़िया

नईदिल्ली। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरबीआई के 2000 का नोट वापस लेने से फैसले से अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि 2000 का नोट वापस मंगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले से अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे वापस हुए नोटों के स्थान पर उसी कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोट जारी कर दिए जाएंगे। पनगड़िया ने कहा कि इस कदम के पीछे संभावित मकसद अवैध धन की आवाजाही को और मुश्किल बनाना है। उन्होंने कहा, हम इसका अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं देखेंगे। 2,000 के नोट की कितनी भी राशि को बराबर कीमत में कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदल दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा। इसलिए धन प्रवाह पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार में 3.5 अरब डॉलर की हुई बढ़ोतरी

मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह में बढ़कर 600 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया।12 मई को समाप्त सप्ताह में यह भंडार 3.553 अरब डॉलर बढ़कर 599.529 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार का जून, 2022 के शुरुआती सप्ताह के बाद का करीब एक साल का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह में भंडार 7.19 अरब डॉलर बढ़कर 595.97 अरब डॉलर पहुंच गया था। अक्तूबर, 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद केंद्रीय बैंक के रुपये में गिरावट थामने के लिए मुद्रा भंडार के उपयोग से इसमें गिरावट आई। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 12 मई वाले सप्ताह में विदेशी मुद्रा संपत्ति 3.577 अरब डॉलर बढ़कर 529.598 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई।

सरकारी बैंकों को 1.05 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा

नई दिल्ली। सभी 12 सरकारी बैंकों का मुनाफा 2022-23 में बढ़कर 1,05,298 करोड़ रुपये के अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इसमें करीब आधी हिस्सेदारी अकेले एसबीआई की है, जो बैंक के मुनाफे के लिहाज से रिकॉर्ड है। वहीं, मार्च अवधि तिमाही में सभी 12 सरकारी बैंकों ने 34,643 करोड़ का मुनाफा कमाया है। खास बात है कि 12 सरकारी बैंकों में से कोई भी घाटे में नहीं है। इन बैंकों के बुरे फंसे कर्जों (एनपीए) में भी गिरावट आई है। इस रिकॉर्ड मुनाफे की कई वजह हैं। एक तो बैंकों ने अपनी बैलेंसशीट को साफ-सुथरा किया है। इस वजह से उन्होंने लाखों करोड़ रुपये के कर्ज को राइट ऑफ कर दिया है यानी उसे अपनी बैलेंसशीट से हटा दिया है। पिछले 6 साल में 9 लाख करोड़ के कर्ज बट्टे खाते में डाले गए हैं। इसके अलावा, कोरोना काल के बाद मांग बढ़ने पर बैंकों ने जमकर कर्ज बांटे। इसके साथ ही खुदरा कर्ज में भी भारी तेजी आई।

नोट वापसी से डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली। आरबीआई के 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा पर केंद्रीय बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा, इस फैसले से कालेधन पर शिकंजा कसने में काफी हद तक मदद मिलेगी और इससे डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, 2016 में मुद्रा को चलन से हटाने का बड़ा कारण अर्थव्यवस्था में कालेधन पर रोक लगाना ही था। गांधी ही 2016 में 500 व 1000 रुपये के नोट चलन से हटाए जाने के समय आरबीआई में मुद्रा विभाग प्रमुख थे। वहीं, पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने कहा कि यह कदम उच्च मूल्य वाले नोटों पर निर्भरता कम करने के लक्ष्य से उठाया गया है और इससे डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, नोटबंदी के बाद जारी किए दो हजार रुपये के नोटों में से आधे पहले ही वापस लिए जा चुके हैं।

टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र योजना की प्रभावी भूमिका

अशोक बजाज

टीबी एक गंभीर जानलेवा बीमारी है. यह अन्य संक्रामक बिमारियों से ज्यादा घातक भी है. बैक्टीरिया से होने वाली यह बीमारी हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में फैलती है। यह आमतौर पर फेफड़ों से शुरू होती है। परन्तु यह ब्रेन, यूटरस, मुंह, लिवर, किडनी, गला, हड्डी आदि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। खांसने और छींकने के दौरान मुंह-नाक से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों से यह इन्फेक्शन फैलता है।

सन 1882 में वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉक ने टीबी रोग के कारक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज करके टीबी रोग उन्मूलन की राह आसान की. आज पूरी दुनिया इस बीमारी से चिंतित है. जानकारों के अनुसार दुनिया में प्रतिदिन 5,200 लोगों की मौत टीबी से होती है जबकि अकेले भारत में हर दिन लगभग 1,400 लोग टीबी से मरते हैं। दुनिया के कुल टीबी मरीजों में 25 प्रतिशत मरीज अकेले भारत में हैं. इसीलिए भारत में टीबी उन्मूलन हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है. सन 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. स्वास्थ व परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का पूरा अमला इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी-जान से जुटा हैं।

देशभर में टी.बी मरीजों की पहचान करके उनके उपचार की उचित व्यवस्था करना तथा उनका समुचित देखभाल करने का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। उपचार अवधि में रोगियों को पोषण युक्त आहार नितांत आवश्यक है. शासन द्वारा डीबीटी के तहत मरीजों के खाते में प्रतिमाह 500 रु हस्तांतरित

किये जा रहे हैं। इसके अलावा RNTCP के तहत सभी रोगियों को टीबी रोधी दवाओं सहित निःशुल्क निदान और उपचार की सुविधा भी प्रदान की गई है।

शासन ने इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की नीयत से एक अभिनव योजना प्रारंभ की है, इस योजना को 'निक्षय मित्र' योजना नाम दिया गया है. इस योजना के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित की गई है यानी टीबी के खिलाफ चल रहे जंग में जनता जनार्दन को भी शामिल कर लिया गया है. निक्षय मित्र योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्थायें मरीजों को पोषण, उपचार व आजीविका में मददगार बनकर प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। इन्हें निक्षय मित्र नाम दिया गया है. निक्षय मित्र को कम से कम एक साल और अधिकतम तीन वर्षों तक रोगियों को गोद लेना होता हैं। परन्तु इसमें टी.बी रोगियो की सहमति आवश्यक हैं। निक्षय मित्र योजना का प्रतिफल यह हुआ कि जन स्वास्थ्य एवं जन सरोकार से जुड़े इस अभियान में लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहें हैं। निक्षय मित्र बनने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति, कारोबारी, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं अर्द्ध सरकारी संस्थाएं आगे आ रही है. टी.बी. उन्मूलन की दिशा में जन भागीदारी बढ़ गई है तथा इस योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप निक्षय पोर्टल www.nikshay.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय हेल्पलाईन नंबर 1800-11-6666 पर भी सम्पर्क किया जा सकता हैं।

कोरोना महामारी के दौर में भारत ने जो महती भूमिका निभाई थी, अब टीबी उन्मूलन की दिशा में भी वही भूमिका दृष्टिगोचर हो रही हैं। देश के वैज्ञानिक भी इसके उन्मूलन के लिए नित नई नई दवाइयां व टीके की खोज कर रहे हैं। इस बिमारी को जड़ से खत्म करना हमारा सबका सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व है. निक्षय मित्र योजना सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई हैं। आइये हम सब निक्षय मित्र योजना में शामिल होकर 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करें।

कर्नाटक जीत से मिला 2024 के लिए जीवनदान

आलोक कुमार

कर्नाटक के चुनावी नतीजों का कांग्रेस के लिए खास महत्व है। कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नए हौसले से भरी कांग्रेस के लिए इस जीत का महत्व कर्नाटक के भीतर ही नहीं बाहर भी है। बिना देवगौड़ा और कुमारस्वामी की मदद लिये कांग्रेस अब कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को तैयार है। इससे विपक्ष में मौजूद शरद पवार, नीतीश कुमार, चंद्रशेखर राव, एम. के. स्टालिन, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सरीखे नेताओं को राजनीतिक झटका लगा है। गुजरात चुनाव में बुरी हार और राहुल गांधी को लेकर खड़े हुए विवादों से शिथिल पड़ी कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश की जीत से वो हौसला नहीं आ पाया था जो कर्नाटक की जीत से आया है। इससे जो गैर कांग्रेसी नेता 2024 में प्रधानमंत्री होने का खूवाब देखने लगे थे, उनमें निराशा बढ़ेगी। इस जीत से क्षेत्रीय दलों द्वारा विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस के हाथ से विपक्ष के नेतृत्व की बागडोर छीनने का विकल्प कमजोर हुआ है। आगे इसी साल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव है। ये विधानसभा चुनाव अगले साल के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे। इन राज्यों में मुकाबला सीधे कांग्रेस और बीजेपी में हैं। मैदान में दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों के अलावा किसी अन्य दल की मौजूदगी नगण्य है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक से खास ऊर्जा से लबरेज कांग्रेस पार्टी आगे बीजेपी से कैसे मुक़ाबला करती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राह के उनके ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट लगातार रोड़े अटकाते रहे हैं और एक बार तो अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने के लिए पूरा प्रयास कर चुके हैं। गहलोत का आरोप है कि कुछ भाजपा नेताओं ने सचिन पायलट को गहलोत सरकार गिराने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे और भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट को राजस्थान का सर्वेसर्वा बनाने की योजना में साथ नहीं दिया और पायलट भी पचास विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद भी सिर्फ 19 विधायकों का समर्थन जुटा सके। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के बागी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की योजना में साथ क्यों नहीं दिया, यह राजनीति के जानकारों के लिए चर्चा का विषय हो सकता है। हालांकि इसके बाद से केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे से नाराज चल रहा है। इसी तरह चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर साय पार्टी छोड़ गए हैं। उन जैसे कई पुराने बीजेपी नेता ऐन मौके पर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शान में कसीदे गढ़ने में लग गए हैं। संघ के पुराने प्रचारक रहे साय को भी उम्र का तकाज़ा देकर सन्यास मार्ग अपनाने पर विवश किया जा रहा था लेकिन फिलहाल उन्हें सन्यास नहीं लेना था इसलिए कांग्रेस में चले गये। इसी तरह शिवराज सिंह के मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए अलग समस्या है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनको अपनी केन्द्रीय कसौटी से बांध रखा है। इसके साथ चुनाव में कांग्रेस से आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं के समर्थकों को टिकट बंटवारे में संयोजित करने की चुनौती है। इसके कारण एमपी बीजेपी में अंदरखाने हलचल तेज है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के और भी कई मायने हैं। अव्वल तो यह मोदी और शाह को संदेश है कि अपने क्षेत्रीय नेताओं और उनकी भावनाओं को आहत न करे। ऐसा करने पर आगे भी उनको कर्नाटक सरीखा ही नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता की पसंद बीएस येदियुरप्पा थे। उनको सत्ता के काबिल इसलिए नही माना गया कि उनकी उम्र 80 साल हो गई। राजनीति में उम्र का यह बंधन न तो येदियुरप्पा से कोई सालभर बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने में आड़े आया, न ही महाराष्ट्र के शीर्ष नेता शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष बने रहने में आड़े आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने येदियुरप्पा की जगह संघ परिवार से आने वाले किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया बल्कि येदियुरप्पा की कथित पसंद के नाम पर जनता दल से भाजपा में आए बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया।

कम होता क्षेत्रीय दलों का प्रभाव

प्रदीप सिंह

कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद से क्षेत्रीय दलों के सुर बदल गए हैं। बात-बात में कांग्रेस को कोसने और राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता न मानने की बात करने वाले अब चुप हैं। राहुल गांधी का मुखर विरोध करने वाले विपक्षी दल अब राहुल गांधी में नेतृत्व देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक विपक्षी गठबंधन की बैठकों में बुलाने के बाद भी आने में आनाकानी करने वाले अब कांग्रेस की शान में कशीदे पढ़ने लगे हैं। इसका कारण सिर्फ कर्नाटक की जीत नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दलों को अब सामने अपनी राजनीति का अवसान दिख रहा है। दो आम चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने पर यही नजर आता है कि जनता छोटे दलों की अवसरवादिता, पदलोलुपता और भ्रष्टाचार के कारण अब इनको धीरे-धीरे राजनीति के मैदान से आउट करना चाह रही है।

मोटे तौर पर कहा जाए तो अब क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक यात्रा पर विराम लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसके साफ-साफ संकेत मिल रहे हैं। दीवाल पर लिखी इस इबारत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे पहले पढ़ा, और कांग्रेस की तरफ सार्वजनिक तौर पर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में हुए उप चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी, और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुस्लिम वोट टीएमसी से खिसक कर कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने लगा है। तबसे टीएमसी में खलबली है और ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस से अपील कर रही हैं कि बंगाल को उनके हवाले छोड़ दिया जाए तो पूरे देश मे वह कांग्रेस के साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कह रहे हैं कि अब देश में गठबंधन की राजनीति का समय खत्म होने जा रहा है। ऐसा कहने के पर्याप्त कारण हैं। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 और 2019 के आम चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। जनता ने अपनी तरफ से पूर्ण बहुमत देने में कोई संकोच नहीं किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो 2017 और 2022 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। अभी हाल में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया। क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस का इस बार न सिर्फ मत प्रतिशत 18.3 प्रतिशत से घटकर 13.29 प्रतिशत हो गया बल्कि 2018 के मुकाबले उसकी सीट भी 37 से घटकर 19 रह गयी। इस तरह कई बार से जनता साफ संकेत और संदेश दे रही है कि उसे कमजोर सरकार नहीं चाहिए, जो विकास कार्यों को रोकने या साफ-सुथरा प्रशासन देने की नाकामी के लिए सहयोगी दलों के मोल-भाव को जिम्मेदार ठहराए। दरअसल, अब जनता को बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ गुड गवर्नेंस चाहिए। उसे कोई बहाना नहीं चाहिए।

क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय जन आकांक्षाओं और जातीय अस्मिता को उभार कर एक समय तक राज किया। लेकिन 1989 से शुरू हुई गठबंधन की उठापटक की राजनीति और सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को जनता समझ चुकी है। क्षेत्रीय और छोटे दलों की राजनीतिक सीमा से भी सब वाकिफ हो गए हैं। ऐसे में आम जनता का झुकाव एक बार फिर राष्ट्रीय दलों की तरफ हो रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। गठबंधन सरकारों के दौर में क्षेत्रीय दल प्रदेश में %स्वतंत्र क्षत्रप% की हैसियत रखते थे तो केंद्रीय सत्ता में %किंगमेकर% की भूमिका निभाते थे। क्योंकि तब केंद्र सरकार छोटे-छोटे दलों को एकजुट करके ही बनती थी। इसके एवज में पहले तो वह राजनीतिक मोल-भाव करते थे, बड़ा और मलाई वाला विभाग मुझे चाहिए, और बाद में समय-समय पर अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सौदा भी करते थे। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, बसपा प्रमुख मायावती, राजद के लालू प्रसाद यादव, एनसीपी के शरद पवार, अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल, तेलगुदेशम के एन. चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक मोल-भाव से सब परिचित हैं। अब देखते हैं कि देश में क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राज्य में कई बार सत्तारूढ़ रहे। इन दोनों दलों की राजनीतिक धमक का असर केंद्र सरकार तक सुनाई देती थी। लेकिन विगत दो विधानसभा चुनाव से सपा विपक्षी दल की हैसियत में तो है, लेकिन बसपा अपना आधार ही गवां बैठी है। बसपा के समक्ष अब अपने अस्तित्व को जिंदा रखने की चुनौती है। वहीं चुनाव दर चुनाव दोनों दलों के मतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पंजाब में यही हाल अकाली दल का है। आम आदमी पार्टी ने अकाली दल की राजनीति और धार्मिक नीति की जड़ें हिलाकर रख दी है। कर्नाटक में यही हाल किंगमेकर देवेगौड़ा की पार्टी जनत दल (सेकुलर) का हुआ है।

महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय भारी उठा-पटक का दौर चल रहा है। राज्य में शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख राजनीतिक दल हैं। शिवसेना भाजपा तो एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाते और चलाते रहे हैं। लेकिन शिवसेना का भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद से ही पार्टी का हर समीकरण बदल गया। शिवसेना में बगावत हुई और अब उद्धव ठाकरे अपनी वाली शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही हाल एनसीपी का है। यदि अजीत पवार पार्टी से विद्रोह कर भाजपा में चले जाते हैं तो संगठन के ज्यादातर कार्यकर्ता अजीत के साथ होंगे। ऐसे में शरद पवार के समक्ष अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में स्थापित करने के लिए कांग्रेस में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती दलित और ओबीसी जातियों का अलग-अलग रूप से राजनीतिक व्यवहार है। जिस तरह से यूपी में सपा और बसपा ओबीसी और एससी की एक विशेष जाति की पार्टी बन कर रह गई, उसके बाद दलितों-पिछड़ों की अन्य जातियों का उनसे मोहभंग हुआ । कुछ जातियां भाजपा तो कुछ कांग्रेस में शामिल हो रही हैं। ठीक इसी तरह क्षेत्रीय दलों को एक झटका उनके मुस्लिम वोटरों से मिलता दिख रहा है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ जाता दिख रहा है। मुसलमानों का मानों क्षेत्रीय दलों से मोहभंग हो गया है और वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का एक बड़ा वोट बैंक उससे छिन रहा है।

एक और कारण है जो क्षेत्रीय दलों की समस्या बन गया है, और वह है परिवारवाद। क्षेत्रीय दलों का नेतृत्व किसी न किसी वंश या परिवार में ही निहित रहता है। जैसे दक्षिण में करुणानिधि परिवार, उत्तर में मुलायम परिवार, लालू परिवार, चौटाला परिवार आदि। एक दौर तक तो उनकी राजनीति ठीक चली लेकिन अब जब परिवार में बिखराव आना शुरु हुआ तो राजनीति भी प्रभावित हो रही है। ऐसे परिवारवादी दलों के सामने संकट अगली पीढी के नेतृत्व का है। स्टालिन हों, अखिलेश हों या तेजस्वी यादव। इनके पास पिता की विरासत तो है लेकिन वैसा करिश्मा नहीं। चौटाला परिवार में तो नेतृत्व की ऐसी कलह मची कि जितने लोग उतनी राह चले गये। ऐसे में क्षेत्रीय दलों का भविष्य संकटग्रस्त दिख रहा है। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह कितना शुभ या अशुभ साबित होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

अश्युपनिषद्

यह उपनिषद् कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है। इसमें महर्षि सांकृति एवं आदित्य के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम से चाक्षुष्मती विद्या एवं योगविद्या पर प्रकाश डाला गया है। यह उपनिषद् दो खण्डों में प्रविभक्त है।

प्रथम खण्ड में चाक्षुष्मती विद्या का विवेचन है। द्वितीय खण्ड में सर्वप्रथम ब्रह्मविद्या का स्वरूप वर्णित है, तदुपरान्त ब्रह्मविद्या प्राप्ति के लिए योग की विविध भूमिकाओं का क्रमशः त्रिवेचन किया गया है। योग की कुल सात भूमिकाएँ हैं, जिनके माध्यम से साधक योग विद्या के क्षेत्र में क्रमिक उन्नति करता हुआ आगे बढ़ता है। सातवीं भूमिका में पहुँचने पर वह ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुँच जाता है। अन्त में ओंकार ब्रह्म के विषय में वह विवेचन प्रस्तुत किया गया है, जिसको जानकर और उस विधि से साधना करके व्यक्ति ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। अपने को परम आनन्दमय-प्रज्ञानघन आनन्द की स्थिति में पाता हुआ मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अनुभूति करने लगता है। यही उपनिषद् का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है।

हे परमात्मन! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें। हम दोनों का साथ-साथ पालन करें। हम दोनों साथ-साथ शक्ति अर्जित करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी (3रखर) हो। हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें। हे शक्ति सम्पन्न! (हमारे) त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) तापों का शमन हो, अक्षय शान्ति की प्राप्ति हो। एक समय की कथा है कि भगवान् सांकृति आदित्य लोक गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने भगवान् सूर्य को नमस्कार कर चाक्षुष्मती विद्या द्वारा उनकी अर्चना की-नेत्रेन्द्रिय के प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्य को नमस्कार है। आकाश में विचरणशील सूर्यदेव को नमस्कार है। हजारों किरणों की विशाल सेना रखने वाले महासेन को नमस्कार है। तमोगुण रूप भगवान् सूर्य को प्रणाम है। रजोगुण रूप भगवान् सूर्य को प्रणाम है। सत्त्वगुणरूप सूर्यनारायण को प्रणाम है। हे सूर्यदेव ! हमें असत् से सत्पथ की ओर ले चलें। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलें भगवान् भास्कर पवित्ररूप और प्रतिरूप (प्रतिबिम्ब प्रकटकर्त्ता) हैं। अखिल विश्व के रूपों के धारणकर्त्ता, किरण समूहों से सुशोभित, जातवेदा (सर्वज्ञाता), सोने के समान प्रकाशमान, ज्योतिःस्वरूप तथा तापसम्पन्न भगवान् भास्कर को हम स्मरण करते हैं। **क्रमशः ...**

नारी समाज के उद्धार के लिए प्रयासरत रहे राजा राममोहन राय

मृत्युंजय दीक्षित

भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक व समाजसेवी ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई सन् 1772 ई. में बंगाल के एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राममोहन के पूर्वजों ने बंगाल के नवाबों के यहां उच्च पद पर कार्य किया किन्तु उनके अभद्र व्यवहार के कारण पद छोड़ दिया। वे लोग वैष्णव सम्प्रदाय के थे। बीस वर्ष की आयु में पूरे देश का भ्रमण किया तथा जानकारी व ज्ञान में वृद्धि की। इस प्रकार अध्ययन कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी योग्यता के बल पर शासकीय जनसेवा के उच्चपद पर पहुंचे। सन् 1803 में पिता की मृत्यु के पश्चात 12 वर्ष के बाद ही नौकरी से मुक्त हो गये। इसके बाद का शेष जीवन कलकत्ते में ही व्यतीत किया तथा पूरा जीवन समाजसेवा को अर्पित कर दिया। सन 1816 में उनके परिवार में एक अत्यंत पीड़ादायक घटना घटी। बड़े भाई की मृत्यु हुई अतः भाई की चिता के साथ ही उनकी पत्नी को चिता पर बैठा दिया गया। इस घटना का उनके मन मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि 1885 में सती प्रथा के विरोध में प्रथम धार्मिक लेख लिखा। एक प्रकार से भारतीय समाज में आचार-विचार को स्वतंत्रता का श्रीगणेश यहीं से प्रारम्भ हुआ। यहीं से समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। सती प्रथा के विरोध में यह उनका प्रथम प्रयास था।

समाज सुधार तथा धर्मसुधार एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते तथा एक में सुधार करने करने के लिए दूसरे में सुधार अपेक्षित है। इस बात का सर्वप्रथम प्रतिपादन राजामोहन राय ने किया। उन्होंने समस्त धार्मिक परिशीलन करते हुए कहा कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और यह ईश्वर रूपी सत्य सभी धर्मों का मत है अत: इसी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ। राजा राममोहन राय ने भारतीय जनमत में परिवर्तन लाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को उपयुक्त एवं आवश्यक बताया। सन् 1827 में हिन्दू कालेज की स्थापना हुई जो बाद में प्रेसीडेंसी कालेज के रूप में विख्यात हुआ। सन् 1830 में एक अंग्रेज यात्री अलेक्जेण्डा उफकों ने अंग्रेजी स्कूल खोलने में सहायता की। राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन तथा प्रकाशन का कार्य किया। राय ने अंग्रेजी, बांग्ला तथा उर्दू में अखबार निकाले। राजा राममोहन राय को स्वतंत्र पत्रकारिता का जनक भी कहा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कठिन संघर्ष किया। राजा राममोहन राय ने धार्मिक एवं सामाजिक विचारों के प्रसार के लिए 20 अगस्त सन् 1828 ईसवीं में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की।

राजा राममोहन राय ने नारी समाज के उद्धार के लिये अनेक प्रयास किये। उनके व्यक्तित्व को महत्व देने के लिये उनके सहयोगियों ने सती होने की अमानुषिक प्रथा को कानून से रोकने का आंदोलन प्रारम्भ किया। यह उनके ही प्रयास का परिणाम था कि 1828 में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया गया। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया था। उनके व्यक्तित्व दृष्टिकोण एवं विचार पर गहन दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उनके विचारों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रसार किया तथा मूर्ति पूजा, बलिप्रथा, भेदभाव, छुआछूत, बहुविवाह एवं सती प्रथा का विरोध किया। वे सभी संस्कृतियों में समन्वय में विश्वास रखते थे। वे धर्मसहिष्णु थे।

पाकिस्तान चार हिस्सों में बँटने जा रहा है

सुरेश हिंदुस्तानी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई के बाद हालात बेकाबू हो रहे हैं। इसके बाद भी उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने उनको प्रकरण में बरी नहीं किया है, केवल जिस स्थान से गिरफ्तार किया, वह तरीका गलत बताया है। इस दौरान पाकिस्तान में जो चला या चल रहा है, उसे किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के लिए हितकारी नहीं माना जा सकता। तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रकार से पाकिस्तान को राजनीतिक आतंक की आग में झोंकने का काम किया है। पिछले कई वर्षों से बेहद दयनीय स्थिति का सामना कर रहे पाकिस्तान में इस प्रकार के हालात उत्पन्न करना अपने स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही कहा जाएगा। इसी कारण पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन और ज्यादा विकराल होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार के विरोध में खतरनाक ढंग से प्रदर्शन करना कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी निरूपित होता जा रहा है। इससे पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा खराब ही होती जाएगी।

पाकिस्तान की विसंगति यही है कि वहां आतंकवाद को खुले तौर पर आश्रय दिया जाता है। आतंकी आकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाली सरकार न चाहते हुए भी उनके संकेत पर कार्य करने के लिए विवश रहती है। इतना ही नहीं पाकिस्तान की सेना भी दूसरे देश के लिए आतंकियों जैसा ही व्यवहार करती है। आज पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए यह सहज ही कहा जा सकता है कि आतंक केवल आतंकवादी ही नहीं फैलाते, बल्कि हर स्तर पर आतंक का सहारा लिया जाता है। अभी जिस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन किया गया, वह प्रदर्शन कम आतंक फैलाने वाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लिए किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले चले हैं। जब कोई नई सरकार बनती है कि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया को राजनीतिक विद्वेष का शिकार होना पड़ा है। वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ भी इसके शिकार हो चुके हैं। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यही कहना तर्कसंगत होगा कि पूरा पाकिस्तान राजनीतिक विद्वेष की अवधारणा को लेकर ही राजनीति कर रहा है।

जहां तक पाकिस्तान की सेना की बात है तो यह सर्वविदित है कि सेना के संरक्षण में ही पाकिस्तान की सरकार बनती है, जैसे ही सरकार सेना के विरोध में आती है, तब पाकिस्तान की सरकार का या तो तख्तापलट हो जाता है या फिर सेना किसी दूसरे दलों को समर्थन देकर नई सरकार बनवा देती है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सत्ता में आई थी, तब इमरान खान की पार्टी को कुछ दलों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था, इस समय सेना का पूरा समर्थन इमरान को प्राप्त था। आज से एक साल पूर्व पाकिस्तान की इमरान खान सरकार को सत्ता से बेदखल कर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इमरान खान के समर्थन में इस बार का प्रदर्शन खतरनाक स्थिति में है। इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि आगजनी की घटनाओं के बाद पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहां सरकारी वाहनों पर खतरनाक ढंग से पत्थरबाजी की जा रही है। जिससे जहां एक ओर आठ से ज्यादा नागरिक और कार्यकर्ता मारे गए हैं, वहीं कई घायल भी हुए हैं। इन घटनाओं से इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़े गृह युद्ध की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह कहना समीचीन होगा कि पाकिस्तान में उसके ही नागरिक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। यानी आतंक भरा वातावरण तैयार करके एक दूसरे के खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे बदहाल देश के लिए इस प्रकार की स्थिति किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस प्रकार की आपसी लड़ाई में पाकिस्तान कभी उबर नहीं सकता। वैसे यह कहा जाना तर्कसंगत ही होगा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि उस समस्या को और ज्यादा विकराल बना देने जैसा ही है। उल्लेखनीय है कि विरोध प्रदर्शन में आगजनी करके शासन, प्रशासन और सेना को ही निशाना बनाने का काम किया गया है। जो यह संकेत करता है कि यह प्रदर्शन सरकार और सेना के विरोध में है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हैं, इन्हें न तो प्रशासन रोक पाने का सामर्थ्य जुटा पा रहा है और न ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता रुकने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यह अस्तित्व की लड़ाई अभी और लम्बी चलेगी। जो वर्तमान सरकार के लिए एक चुनौती बनेगी ही, साथ ही पाकिस्तान के रास्ते में बड़ा अवरोध भी बन सकती है।

अपने जन्म काल के समय से पाकिस्तान अपने हुक्मरानों की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है। वर्तमान की स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान की जनता महंगाई के दलदल में फंसती जा रही है। पाकिस्तान को जिन देशों से आस थी, वह आस भी अब टूटने लगी है। चीन ने पाकिस्तान को ऐसी जगह छोड़ दिया है, जिसकी एक ओर कुआँ है तो दूसरी तरफ खाई है। यानी पाकिस्तान जिधर भी जाएगा, उस तरफ उसकी दुर्गति ही होनी है। दूसरा एक नया संकट पाकिस्तान में यह भी उभर रहा है कि उसके राज्यों में स्वायत्त देश बनाने की मांग भी उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान चार हिस्सों में बंट जाएगा। इसमें से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भारत के प्रति सकारात्मक आवाजें आ रही हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पाकिस्तान ने 75 साल पूर्व जो भूल की थी, आज उस भूल को सुधारने का प्रयत्न करने की ओर अग्रसर हो रहा है। पाकिस्तान के कई नागरिक पहले भी खुले तौर पर कह चुके हैं कि आज पाकिस्तान की दुर्गति को देखकर यही लगता है कि हम हिन्दुस्तान के साथ ही रहते।

बापू की दिनचर्या

रोगी-सेवा और चिकित्सा (भाग-2)

बापू के आश्रमों में कुष्ठ और चेचक सरीखे संक्रामक रोगग्रस्त जनों की और भी लगन से सेवा की जाती। जिन रोगों को समाज में भयंकर और अत्यंत घृणित समझा जाता और जिनसे पीड़ित रोगी स्पर्श के योग्य नहीं माने जाते. ऐसे रोगी बापू के विशेष कृपाभाजन होते। वे कुष्ठ रोगी को औरों की तरह कभी हेय दृष्टि से नहीं देखते और न उसके लिए कभी बदनाम शब्द का प्रयोग होने देते, अपितु उसे समाज का अंग बताते। ऐसे लोगों की सेवा-शुश्रूषा, सार-सँभाल पर वे बहुत जोर देते, उनकी उपेक्षा देखकर उनके दिल पर काफी चोट पहुँचती। इसी प्रकार रोगियों में धनी-निर्धन या अपने-पराये का भेद उनमें तनिक नहीं था। उनकी यह धारणा दृढ़ थी कि स्वच्छ शरीर और निर्मल अंतःकरण वाले को ऐसे जनों के संसर्ग से कोई बाधा नहीं पहुँच सकती। अपनी इसी प्रवृत्ति से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर सन् 1896-97 में राजकोट में प्लेग-निवारण में बापू ने मदद की। कोचरब-आश्रम में दक्षिण अफ्रीका के वीर सत्याग्रही मारीशस निवासी थंबी नायडू के पुत्र फकीरी नायडू, जो विद्यार्थी-रूप में रहते, बड़ी चेचक से ग्रस्त हो गए तो मवाद से सने उनके वस्त्र बापू स्वयं अपने हाथों सुबह-शाम बदलते और उन्हें शुभ्र श्वेत चादर ओढ़ाते। मवाद से सने कपड़ों को उठाने, पानी में उबालने एवं उन्हें धोने सुखाने में भी वे खुद भाग लेते। वहाँ देवदास भाई। भी इसमें बापू का हाथ बंटाते। युवा बापू जब सन् 1901 में मारीशस में कुछ समय तक रहे, थंबगी नायडू उनसे प्रभावित होकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह में सपत्नीक भाग लिया तथा जेलयात्रा की। बापू जब दक्षिण अफ्रीका छोड़ने लगे, तब थंबी नायडू ने अपने चारों पुत्र बापू को सौंप दिए। बापू के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा था कि इन रत्नों को खोकर भारत लौट रहा हूँ, किंतु वे मुझे मिल गए। मारीशसीय समझते हैं कि मारीशस के एक व्यक्ति ने एक ऐतिहासिक अवसर पर बापू को अपूर्व दान दिया था। साबरमती में सायंकालीन प्रार्थना के पश्चात् आश्रम के प्रायः सभी बीमारों का हाल, प्रार्थनासभा में आनेवाले उनके घरवालों या पड़ोसियों से पूछने का बापू का नित्य का नियम था। किसी का समाचार न मिल पाता या कोई अधिक अस्वस्थ होता, तो वे खुद जाकर देखते। अपने परिचितों के घर में किसी की बीमारी की बात सुनकर वे उनके यहाँ देखने अक्सर पहुँच जाते।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक 25 को

बीजापुर। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 25 मई को सुबह 11 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आहूत की गयी है। बैठक में वन, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ईत्यादि विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उक्त बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अद्यतन जानकारी सहित उपस्थित होने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला पंचायत सदस्यों एवं मानद सदस्य सर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष को इस बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ आज से

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में भी समाचार बुलेटिन रविवार से शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन 21 मई की शाम राजभवन रायपुर से इस समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी। गोंडी बोली में यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन जगदलपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र से हर रविवार शाम साढ़े छह बजे से मीडियम वेव पर 756 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बीते मार्च महीने से जनजातीय बोली हल्बी में भी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू कर चुका है। हल्दी में प्रसारित किए जा रहे इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ बीते 25 मार्च को जगदलपुर से केंद्रीय गृह अमित शाह ने किया था।

10 जून को सहायक शिक्षक व शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन

महासमुंद। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक एवं शिक्षक ई एवं टी संवर्ग की भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापमं द्वारा शनिवार 10 जून को दो पालियों में किया जाएगा। व्यापमं के अनुसार प्रथम पाली में शिक्षक एवं द्वितीय पाली में सहायक शिक्षक भर्ती हेतु परीक्षा ली जाएगी। कलेक्टर ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती ऋतु हेमनानी को नोडल अधिकारी बनाया है।

सीजीपीएससी सिविल जज मुख्य परीक्षा कार्यक्रम घोषित

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2022 के लिए मुख्य परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा 27 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित की जानी है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in से परीक्षा से 10 दिन पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 521 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 48 रिक्तियों को भरना है। सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा 2022 में तीन राउंड शामिल होंगे - प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार इत्यादि। डाउनलोड करने के चरण- सबसे पहले उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं। होम पेज पर सिविल जज मेन एग्जाम शेड्यूल पर क्लिक करें। सीजीपीएससी परीक्षा का शेड्यूल स्क्रीन पर दिखाई देगा। सिविल जज (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2022 का शेड्यूल देखें और डाउनलोड करें। भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंट आउट ले लें।

प्रथम थ्री फेज प्रणाली मेमू रेक का निरीक्षण, यात्री जल्द करेंगे सवारी

भिलाई। छत्तीसगढ़ के रेलवे ट्रैक पर जल्द ही नई मेमू दौड़ेगी। रेलवे यात्री जल्द ही इस नई मेमू की सवारी कर सकेंगे। इस मेमू में कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बीते दिनों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने मेमू कार शेड भिलाई में प्रथम थ्री फेज प्रणाली मेमू रेक का निरीक्षण किया। इस नई मेमू रेक का परिचालन जल्द ही शुरू होगा। इसके शुरू होने से आम जनता को यात्रा में काफी सहूलियत मिलेगी। यह मेमू रेक आधुनिक एवं सर्वसुविधायुक्त है, जिसमें पब्लिक अनाउंसमेंट, डिस्प्ले सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट एवं सीसीटीवी कैमरे से लैस है। जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। सभी कोच में बायो टॉयलेट उपलब्ध हैं, जिससे लंबी दूरी यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। इस नई तकनीक से ट्रेन की स्पीड एवं ब्रेकिंग सरलता से हो सकेगी। बता दें कि इस रेक में रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे ऊर्जा संरक्षण भी होता है। इस निरीक्षण के दौरान मुख्य विद्युत इंजीनियर, आरके साहू, शशांक कोष्टा एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर 25 को शहीदों को किया जाएगा नमन

कोरबा। झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सली हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए सभी लोगों की स्मृति में 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर नक्सली हिंसा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया जाएगा।

सांकरा पाटन में 120 करोड़ की लागत से बनेगा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विवि भवन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे शिलान्यास

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मई को दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के भव्य प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवनों सहित छात्रावास, अनुसंधान केन्द्र भवन, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भवनों के निर्माण का कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण 119 करोड़ 90 लाख 77 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं को उद्यानिकी एवं वानिकी आधारित विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए इस विश्वविद्यालय की शुरूआत 02 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय के अधीन राज्य में कुल 18 उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित है, जिसमें 14 शासकीय एवं 4 अशासकीय महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय के अधीन सांकरा में उद्यानिकी एवं वानिकी के पृथक-पृथक महाविद्यालय संचालित है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु उद्यानिकी एवं वानिकी के लिए बेहद अनुकूल है। राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी को बढ़ावा देने के साथ ही इसके जरिए युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसकी विशेष शिक्षा के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही डिग्री भी दी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में पीएचडी भी कराई जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में स्नातक फाइनल ईयर का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन सांकरा में 44.52 करोड़ रूपए की लागत से शैक्षणिक भवन, 10.01 करोड़ रूपए की लागत से संचालनालय भवन, 9.99 करोड़ रूपए की लागत से प्रशासनिक भवन, 95 लाख की लागत से कुलपति आवास तथा 6 करोड़ 7 लाख रूपए की लागत से आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में 3.47 करोड़ रूपए की लागत से 100 सीटर स्नातक बालिका छात्रावास, 4.77 करोड़ रूपए की लागत से 100 सीटर स्नातकोत्तर बालक छात्रावास, 3.47 करोड़ रूपए की लागत से 100 सीटर स्नातक बालक छात्रावास, 2.69 करोड़ की लागत से किसान छात्रावास, 48 लाख रूपए की लागत से सामुदायिक भवन, 56 लाख रूपए की लागत से बैंक एवं पोस्ट ऑफिस भवन, 7.6 करोड़ रूपए की लागत से इंडोर स्टेडियम, 7 करोड़ रूपए की लागत से उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र का प्रशासनिक भवन, 5.92 करोड़ रूपए की लागत से 75-75 सीटर बालक-बालिका छात्रावास तथा 12 करोड़ रूपए की लागत से वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक भवन सहित छात्रावास भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

कोरबा में मजदूरों ने किया प्रदर्शन रोका जाए नियमों का उल्लंघन

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल की भूमिगत खदान में पिछले दिनों हुए हादसे के बाद मजदूरों का गुस्सा भड़क गया है। सुरक्षा को लेकर खदान मजदूरों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। कहा कि, खदानों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसे रोका जाए और मानकों का सख्ती से पालन हो। इसके लिए उन्होंने प्रबंधन के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। मजदूरों ने 22 मई को गेवरा खदान में प्रदर्शन का एलान किया है। कहा कि, सुरक्षा संबंधी मांगों को लेकर प्रबंधन का ध्यानाकर्षण करवाया जाएगा।

दरअसल, चार दिन पहले एसईसीएल की बगदेवा कोल परियोजना में हादसा हुआ था। इसमें ऑपरेटर सहित दो श्रमिक घायल हो गए थे। इसके बाद शनिवार को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के बैनर तले मजदूर कुसमुंडा खदान में एकत्र हो गए और प्रदर्शन करने लगे। झंडा और बैनर लेकर पहुंचे मजदूरों ने नारेबाजी की। मजदूरों का कहना था कि, पिछले दिनों बगदेवा कोल परियोजना में जिस तरह से हादसे के दौरान दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, इससे एक बार फिर चिंता सताने लगी है।

मजदूरों ने इस दौरान पांच सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा

खदान के भीतर सुरक्षा नियमों के हो रहे उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाई जाए। सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। डीजीएमस द्वार नियमित रुप से खदान का निरिक्षण किया जाए। कोल इंडिया कंपनी, क्षेत्रीय कंपनियों की सुरक्षा ईकाई की बैठकें नियमित रूप से हों। खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए दोषी लोगों के खिलाफ अनुशास्नात्मक कार्रवाई की जाए।

युवाओं को मताधिकार का अधिकार राजीव की देन: महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने 21वीं सदी के प्रणेता कंप्यूटर क्रांति के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुये नमन किया है। कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। विस् अध्यक्ष डॉ महंत ने कहा कि, राजीव गांधी जी देश के युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता थे, उनका भाषण सुनने के लिए लोग काफी इंतज़ार भी करते थे।

डॉ महंत ने कहा कि 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा और नौवें प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले राजीव गांधी आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जा सकते हैं। वह पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने देश में तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता देकर कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर जोर डाला। भारत में कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए उन्हें कई विरोधों और आरोपों को भी झेलना पड़ा, लेकिन अब वह देश की ताकत बन चुके

उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐसे फैसले लिए जिसका असर देश के विकास पर देखने को मिला। शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। राजीव ने कई साहसिक कदम उठाए जिनमें श्रीलंका में शांति सेना का भेजा जाना, असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल है।

दूसरी नोटबंदी कहना उचित नहीं

रायपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट का प्रचलन बंद करने का ऐलान क्या किया हल्ला मच गया। बैंक अब दो हजार के नए नोट नहीं देगा। जो पुराने हैं उन्हे बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक चार माह का समय दिया गया है जो कि पर्याप्त है। वैसे एक बात साफ है कि आम लोगों के पास नहीं मिलेगा 2 हजार का नोट। उच्च वर्ग के लोगों के पास ही है,लेकिन सोशल मीडिया में ऐसा माहौल बना दिए कि जैसे नोटबंदी हो गई है। दूसरी नोटबंदी तो कतई नहीं मान सकते। बैंकों में पर्याप्त काउंटर लगाने का निर्देश है,वहीं यह भी स्पष्ट है कि नोट अमान्य नहीं किया गया है। हां ..यह कहा जा सकता है कि 20 हजार की जो लिमिट है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। उनके लिए जिनके पास जीएसटी नंबर है इससे व्यापारिक तबके को राहत मिलेगी। जब डिजिटल पैमेंट को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो ऐसे नोटों के प्रचलन बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विभिन्न सेक्टर के लोगों से जब रायशुमारी की गई तो उनका भी मानना है कि इसे नोटबंदी नहीं कह सकते हैं और न ही कोई फर्क पड़ेगा।

सोच बदल लो, जीवन बदल जाएगा : शक्तिराज सिंह

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा विधानसभा मार्ग स्थित शान्ति सरोवर में आयोजित जिन्दगी का उत्सव नामक तीन दिवसीय शिविर के दूसरे दिन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा विषय पर व्याख्यान हुआ। इन्टरनेशनल माइण्ड व मेमोरी मैनेजमेन्ट ट्रेनर ब्रह्माकुमार शक्तिराज सिंह ने कहा कि हमारे विचारों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी सोच को बदल लो तो जीवन बदल सकता है। अनुसंधान से पता चला है कि हमारे मन में पूरे दिन भर में साठ हजार के लगभग विचार पैदा होते हैं जिसमें से साठ प्रतिशत फालतू (व्यर्थ) होते हैं। अब हमें इन विचारों की गति को कम करना है। ताकि हमारी शक्ति व्यर्थ में खत्म न हो। उन्होंने आगे कहा कि लोगों के पास सोफासेट, ड्राईंग सेट, क्राकरी सेट, ज्वेलरी सेट आदि सभी सेट रखे हुए हैं लेकिन माउण्ड सेट नहीं है। वह अपसेट पड़ा हुआ है।

उन्होंने बताया कि यदि हम न चाहें तो कोई भी व्यक्ति हमें परेशान व दुखी नहीं कर सकता है। लोग तो कमेन्ट करेंगे परन्तु जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब दुःखी होते हैं। यदि लोगों की निगेटिव बातों को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। हमें अपनी खुशियों का रिमोट कन्ट्रोल अपने हाथ में रखना चाहिए। दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगेटिव एनर्जी से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। घर में यदि कलह-क्लेश है इसका मतलब है कि बैटरी डिस्चार्ज है। मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा को याद करने से परमात्म शक्ति हमें प्राप्त होती है। उन्होंने बतलाया कि यदि लगातार इक्कीस दिनों तक खराब रिलेशन वाले व्यक्ति को पाजिटिव वायब्रेशन दिए जाएं तो उसके प्रभाव से खराब रिलेशन भी ठीक हो जाते हैं।

उन्होंने निगेटिविटी को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बतलाते हुए कहा कि हम सभी आत्माएं एक पिता परमात्मा की सन्तान होने के कारण आपस में भाई-भाई हैं। जब यह ईश्वरीय ज्ञान हमें मिल जाता है और हम सामने वाले को जो है जैसा है स्वीकार कर लेते हैं तो अस्सी प्रतिशत झगड़ा समाप्त हो जाता है। आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है। वह शरीर के द्वारा कर्म करती है। हम सारे दिन में जितने भी लोगों के सम्पर्क में आते हैं उनके साथ हमारा कार्मिक एकाउण्ट बनता जाता है।

छत्तीसगढ़ में हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन के लिए होगा वृहद स्तर पर पौधों का रोपण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा चालू वर्ष 2023 में वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन के लिए वृहद स्तर पर 02 करोड़ 91 लाख 20 हजार पौधे के रोपण एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप उक्त वृहद वृक्षारोपण अंतर्गत अधिक से अधिक फलदार पौधों का रोपण के कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि विभागीय योजनांतर्गत 7065 हेक्टेयर तथा 20 कि.मी. में 64 लाख 64 हजार पौधे, मनरेगा अंतर्गत 70 हेक्टेयर एवं 60 कि.मी. में 90 हजार 800 पौधे, कैम्पा अंतर्गत 4016 हेक्टेयर में 22 लाख 27 हजार पौधे एवं अन्य योजनांतर्गत 80 हेक्टेयर में 2 लाख पौधों के रोपण से राज्य हरितिमा से आच्छादित होगा। उल्लेखनीय है कि वृक्षारोपण अंतर्गत 59 लाख 76 फलदार पौधे जिसमें आम, जामुन, बेल, कटहल, मुनगा, सीताफल, पपीता, अनार, नींबू, शहतूत, बादाम, बेर, तेन्दू, गंगा ईमली, लीची, आदि प्रजाति के पौधों का रोपण एवं 67 लाख 49 हजार लघु वनोपज एवं वनौषधि जैसे पुत्राजीवा, काला सिरस, सिंदूरी, गरूड़, रीठा, चित्राक, एलोविरा, गिलोय, अडूसा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, छोटा करोंदा आदि प्रजाति तथा 30 लाख 42 हजार बांस के पौधों का रोपण एवं वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक नदी तट रोपण के तहत विगत वर्षों की भांति आगामी वर्षा ऋतु में भी प्रदेश की हसदेव, गागर, बांकी, बधुरा, बनास, जमाड़, महानदी, शिवनाथ तथा खारून नदियों के तटों पर 410 हेक्टेयर एवं 10 कि.मी. में लगभग 3 लाख 46 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा, जो न सिर्फ मृदा कटाव को रोकेगा, साथ ही छायादार, फलदार एवं अन्य बहुउद्देश्यों की पूर्ति भी भविष्य में स्थानीय नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप करेगा। वहीं प्रदेश के मार्गों के किनारे हरियाली को बढ़ाने की दृष्टि से सड़क किनारे वृक्षारोपण अंतर्गत 45 कि.मी. लंबाई के मार्ग में 43 हजार पौधों का रोपण भी किया जाएगा।

आप ने भूपेश पर लगाया आरोप

मुख्यमंत्री के बेटे के पास पहुंचा उगाही का पैसा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही कार्रवाई और कथित शराब घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने कहा कि, ईडी ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तर पर चलने वाले उगाही रैकेट का भंडाफोड़ किया है। चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू तक उगाही का पैसा पहुंचाया गया। आरोप लगाया कि, मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को फायदा पहुंचाया और अरबों रुपये बिट्टू तक पहुंचाए गए।

रायपुर में आप अध्यक्ष हुपेंडी ने कहा कि, सीएम भूपेश चुप क्यों हैं। वह अपनी चुप्पी तोड़ें, मुख्यमंत्री मीडिया में जवाब दें। कहा कि, चुप्पी का मतलब है कि दो हजार करोड़ के शराब घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध है। कांग्रेस से अब तक किसी नेता का बयान सामने नहीं आया। ईडी की चार्जशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चार्जशीट में सीएम की अधिकारी रहीं सौम्या चौरसिया का नाम भी शामिल है।

चिरायु से जन्मजात पैर की विकृति से ग्रसित बच्चों का इलाज हुआ संभव

सारंगढ़-बिलाईगढ़। चिरायु दल बरमकेला द्वारा आंगनबाड़ी में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पैर की विकृति (क्लब फुट) से ग्रसित कई बच्चों का चिन्हांकन किया गया। उनके परिजनों को अवगत कराया गया कि उचित समय में इलाज करा लेने पर विकृत पैर सामान्य हो सकता है। चिरायु दल द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के फलस्वरूप बच्चों के परिजनों ने इलाज हेतु तत्परता दिखाई। इस प्रकार जिला अस्पताल रायगढ़ में प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाले क्लब फुट डे शिविर में ग्राम कंडोला निवासी कृष्णा चौहान उम्र 4 महीना पिता टीकाराम चौहान, ग्राम भीखमपुरा के शबिर सिदार उम्र 4 महीने पिता बिलाईगढ़िया सिदार, ग्राम तरेकेला के सचिन कोडाकू उम्र 6 वर्ष पिता गजेंद्र कोडाकू, ग्राम मेड्रा के तेजस पटेल उम्र 3 महीना पिता अशोक पटेल, ग्राम अडभार के पायल चौहान उम्र 2.5 वर्ष पिता रूपचंद चौहान तथा प्रीतम खड़िया उम्र 3 वर्ष उत्तरा कुमार खड़िया को इलाज के लिए ले जाया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा जांचोपरांत उचित सलाह दी गई एवम इनमें से एक बच्चे के पैर की कास्टिंग प्रक्रिया की गई तथा जरूरतमंद बच्चों को करेक्शन शूज निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। चिरायु के समस्त कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एफ. आर. निराला, डी. पी. एम. श्री एन. एल. ईजारदार, चिरायु नोडल अधिकारी डॉ. प्रभुदयाल खरे, खंड चिकित्सा अधिकारी बरमकेला डॉ. अवधेश पाणिग्राही, बी.पी.एम. श्री ईश्वर प्रसाद दिनकर, चिरायु टीम के डॉ. सुरेन्द्र सिंह, डॉ. हेमलता रायसागर आदि का सहयोग रहा।

प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हो कार्यकर्ता निष्ठा से करें काम : यादव

आगामी विस चुनाव के लिए पदाधिकारियों से एक-एक कर मांगे सुझाव

राजनांदगांव। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन द्वारा 19 मई शुक्रवार को स्थानीय एबीस ग्रीन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई। जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व छग सहप्रभारी डा.चंदन यादव द्वारा यह बैठक ली गई।

जानकारी देते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने बताया कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार जिला स्तर पर बैठक का आयोजन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव डा.चंदन यादव ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रत्येक पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उनसे सुझाव मांगे और आगामी चुनाव के लिए जुट जाने के लिए कहा।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव डा.चंदन यादव ने पदाधिकारियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत की वजह से ही 2018 में बहुमत की सरकार बनाई है इसे बरकरार रखते हुए 2023 में और अधिक विधानसभा की सीटें जीताकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहराना है और यहां के कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। इस हेतु प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार सत्तासीन हो कार्यकर्ता निष्ठा से काम करें। उन्होंने आगे कहा कि यह शहर जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रमुख पदाधिकारियों को आने वाले चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का निर्धारण और संगठन में कसावट लाने और विधानसभा चुनाव तक मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप देना है।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रदेश महामंत्री शहर कांग्रेस प्रभारी अरूण सिसौदिया ने उपस्थित पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने व लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले इस हेतु कार्य करना हर कार्यकर्ता का प्रमुख दायित्व है। पुराने कांग्रेसजनों को फिर से सक्रिय करने को लेकर जिम्मेदारी देने की बात कहीं है।

बैठक में उपस्थितजनों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए संगठन के कार्यकर्ता संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए बूथ स्तर तक शासन की योजनाओं को पहुंचा रहे है और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने में सफल हुए है।

संवैधानिक संस्था पर राजनीति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग याने पीएससी फिर सुर्ख़ियों में है। इस बार भी चयन सूची को लेकर विवाद है। वैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का विवादों से पुराना नाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किसी संवैधानिक संस्था का इस प्रकार बार-बार विवादों में रहना राज्य के हित में नहीं माना जा सकता। विवादस्पद संस्था से सलेक्ट लोकसेवक कैसे लोकहित में काम करेंगे,यह बड़ा सवाल है। सरकार किसी भी दल की रहे, राज्य की मशीनरी को चलाने वाले जहां से निकलते हैं, वहां थोड़ी सी आंच पर जांच करा लेनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी कर लेना चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस बार विवाद के साथ राजनीति भी खूब हो रही है और राजनीतिक दल एक-दूसरे के कपड़े उतारने में लग गए हैं। पीएससी को पाक-साफ़ करने में किसी की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। पानी में लाठी पीटने की जगह पीएससी के माथे पर लगे कालिख को धोने का प्रयास होना चाहिए।

मंत्री रूद्र गुरु खफा क्यों ?

चर्चा है कि पीएचई मंत्री रुद्रकुमार गुरु बड़े खफा हैं और वे अपनी बात कांग्रेस की प्रभारी महासचिव सुश्री सैलजा के सामने रखना चाहते थे, पर रख नहीं पाए। कहते हैं पीएचई विभाग में मंत्री के पसंद के न तो सचिव हैं और न ही जल जीवन मिशन के प्रबंध संचालक। पीएचई विभाग के ईएनसी

रवि भोई

मगनलाल अग्रवाल पहले हटाए जा चुके हैं। विभाग में कोई बड़े अफसर न होने के कारण अग्रवाल साहब को फिर ई एन सी का चार्ज मिल गया। कहा जाता है कि पुराने ईएनसी टी जी कोसरिया और जल जीवन मिशन के प्रबंध संचालक आलोक कटियार में पटरी नहीं बैठने के कारण मंत्री रूद्र गुरु की कुछ चल जाती थी। पीएचई के ईएनसी जल जीवन मिशन के एडिशनल प्रबंध संचालक भी होते हैं। खबर है कि जल जीवन मिशन में करीब दो हजार करोड़ के टेंडर जारी हुए हैं। टेंडर जल्दी खोलकर काम भी फटाफट किए जाने हैं।

भाजपा के नेता पसोपेश में

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को छह महीने बचे हैं और नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाजपा का चुनावी कमान किसे सौंपा जाय। भाजपा हाईकमान ने ओम माथुर, अजय जामवाल और नितिन नबीन को रणनीतिकार और मार्गदर्शक के तौर पर छत्तीसगढ़ भेजा है। अभी ये बैठकों से उबर नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा की हार के बाद माना जा रहा है कि लोकल नेताओं को तवज्जो मिलेगा और हाईकमान अपना निर्णय थोंपने के रुख में बदलाव करेगा। अब देखते हैं क्या होता है , पर भी तो नेता असमंजस में हैं कि चुनाव की कमान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमनसिंह को सौंपे या दूसरे किसी नेता को। कहते हैं चुनाव की कमान संभालने के लिए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और आदिवासी नेता रामविचार नेताम भी इच्छुक हैं।

ईडी फीवर

कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को ईडी फीवर हो गया है। इस फीवर से सबसे ज्यादा परेशान चर्चित अफसर,नेता और बड़े कारोबारी हो रहे हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा है। कहा जा रहा है कि ईडी का नोटिस मिलने के बाद एक अफसर बयान देने जाने की जगह अस्पताल में भर्ती हो गए। लोग कह रहे हैं कि भरपूर मलाई खाने के बाद छाछ को भी नहीं छोड़ने से ऐसा तो होना ही था। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए एक कारोबारी भी अस्पताल पहुंच गए। नायक फिल्म के एक दृश्य की तरह कहीं ईडी लाव-लश्कर के साथ अपने वांटेड लोगों से पूछताछ करने के लिए अस्पताल न पहुंच जाय और उंगुली टेढ़ी न कर दे।

क्या कोरबा के कलेक्टर-एसपी बदलेंगे ?

कहते हैं कोरबा के कलेक्टर संजीव झा और एसपी यू उदय किरण से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल बड़े नाराज हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रभारी महासचिव सुश्री सैलजा की बैठक में मंत्री जी ने कलेक्टर-एसपी द्वारा उनकी अनसुनी का मुद्दा उठाया था। अब कहा जा रहा है कि कोरबा के कलेक्टर और एसपी को जल्दी ही बदला गया तो मतलब साफ़ होगा कि मंत्री जी की बात सुनी गई और नहीं बदला गया तो संकेत होगा मंत्री जी वजनदार नहीं हैं। कलेक्टर रानू साहू की भी मंत्री जयसिंह अग्रवाल से पटरी नहीं बैठ पाई थी।

कुछ नेता ईडी के निशाने पर

कहा जा रहा है मई का आखिरी सप्ताह कुछ नेताओं पर भारी पड़ सकता है। खबर है कि ईडी राज्य के कुछ नेताओं पर सख्ती बरत सकती है। ईडी ने पिछले हफ्ते कुछ नेताओं और अफसरों को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। कुछ कारोबारियों को भी बुलाया था। एक जनप्रतिनिधि को भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा है। नोटिस के बाद भी एक अफसर हाजिर नहीं हुए। ईडी के रुख का लोगों को इंतजार है।

क्या अरविंद नेताम भाजपा में जाएंगे

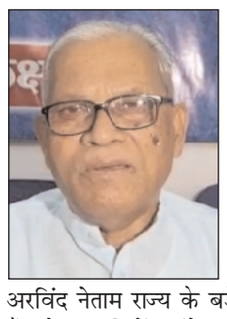

कहते हैं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम राज्य के बड़े चेहरों में से एक हैं। वे इन दिनों कांग्रेस से खफा हैं। सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले नेताम जी अपना ताल ठोंक रहे हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज का उम्मीदवार खड़ाकर नेताम जी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। कांग्रेस ने भाजपा के आदिवासी चेहरा नंदकुमार साय को तोड़कर राज्य की राजनीति को गरमा दी है। कहते हैं अब भाजपा अरविंद नेताम को साधकर कांग्रेस को पटखनी देने की रणनीति पर चल रही है। खबर है कि पिछले दिनों भाजपा के प्रभारी ओम माथुर और अरविंद नेताम की लंबी चर्चा भी हो चुकी है।

प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा

पिछले दिनों कांग्रेस की प्रभारी महासचिव सुश्री सैलजा की मंत्रियों और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक के बाद राज्य में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा है। कहते हैं इस बैठक में कई मंत्रियों ने अपने विभाग में अपने पसंद के सचिव न होने और जिले में मनपसंद कलेक्टर-एसपी न होने की बात की। कहते हैं एक मंत्री ने तो अपने विभाग में पसंद के अफसर न होने पर इस्तीफा देने की बात कह दी , वहीं एक मंत्री ने अफसरों द्वारा उनकी जमीन नपवाने की बात की। इस फेरबदल में कलेक्टर-एसपी के साथ कई विभाग के सचिव भी इधर-उधर हो सकते हैं।

रतनपुर में पुलिस के खिलाफ सड़क उतरी जनता

बिलासपुर।. प्रदेश में सामाजिक सद्भाव का वातावरण लगातार बिगड़ रहा है। कवर्धा में झंडा विवाद से लेकर बीरनपुर में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद अब रतनपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है और इसके लिए लोग पुलिस प्रशासन को दोषी मान रहे हैं। रतनपुर क्षेत्र में एक हिंदू लड़की का बलात्कार करने का आरोप आफताब मोहम्मद पर लगा है। इस मेपुले में पीड़ित लड़की की मां पर पुलिस की द्वेषपूर्वक कार्रवाई के कारण लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. नाराज लोगों ने शनिवार शाम को रतनपुर थाने का घेराव कर दिया. रविवार को रतनपुर बंद का आह्वान किया गया है.इस पूरे विवाद की कहानी करीब ढाई महीने पहले शुरू होती है, जब एक युवती को आफताब मोहम्मद (19 वर्ष) नाम का युवक अपने प्रेम जाल में फंसाता है. उससे खुंटाघाट में दुष्कर्म करता है, फिर मारपीट कर उसे बदहवास हालत में छोड़कर भाग जाता है. पुलिस इस मामले में आफताब को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है. इससे पहले पीड़ित युवती और उसकी विधवा मां को पहले पैसे का लालच देकर समझौते का दबाव बनाया जाता है, फिर डराया धमकाया जाता है.

जब दोनों अपनी बात पर कायम रहते हैं तो पीड़ित की मां जो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, को पूछताछ के नाम पर थाने बुलाया जाता है और आनन फानन में गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाता है। जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है. महिला पर आफताब के रिश्तेदार के दस साल के बालक का यौन शोषण करने का आरोप लगाया जाता है.

सरकार ने किया लालू चारा से बड़ा गोठान घोटाला: भाजपा

- **पूरे छत्तीसगढ़ में चलबो गोठान, खोलबो पोल अभियान शुरू***
- **न कहीं चारा, न कहीं गोबर, न ही गोधन, डकार रहे जनता का धन***

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा का चलबो गोठान, खोलबो पोल अभियान शुरू हो गया है। पहले ही दिन भाजपा नेताओं ने राज्य भर में विभिन्न स्थानों में गोठानों का निरीक्षण कर वहां चल रहे भारी अंधेरगर्दी, धांधली, अनियमितता और भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। भाजपा नेताओं को कई गोठानों में एक भी गाय नहीं मिली। न चारे का इंतजाम दिखा, न गोठानों के रिकार्ड में उस बड़े पैमाने पर गोबर की बिक्री दर्ज है, जिस बड़े पैमाने पर सरकारी रिकार्ड में खरीदी और भुगतान हो रहा है। कहीं शेड बनाने के बाद काम बंद कर दिया गया है तो कहीं कम गोबर खरीदी को बढ़ा चढ़ाकर बोगस भुगतान कर सरकार के खजाने को लूटा जा रहा है। यदि गोठान समितियों के रिकार्ड और सरकार के भुगतान के रिकार्ड का मिलान कर लिया जाए तो हजारों करोड़ का गोठान और गोबर घोटालेबाजी सामने आ जायेगी। भाजपा गोठानों का भौतिक निरीक्षण कर इसी भ्रष्टाचार को उजागर करने गांव गांव अभियान पर निकली है।

भाजपा के प्रदेश व्यापी अभियान के तहत नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के नैला गोठान का निरीक्षण किया। गोठान में भारी अव्यवस्था नजर आई। गोठान में एक भी गाय नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि गोठानों में गोबर घोटाले के साथ साथ कई तरह के घोटाले चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिहार से बड़ा चारा घोटाला भूपेश बघेल सरकार में चल रहा है। गोबर खरीदी के नाम पर धांधली चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता का धन बांटकर भूपेश बघेल गोबर गाथा का प्रचार कर रहे हैं जबकि हकीकत यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला चल रहा है।

प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने भानपुरी मंडल के घोटिया,सुदापाल, पाथरी,मुरकुची के गोठन में जाकर अवलोकन किया। सभी गोठानो की हालत गंभीर है कोई लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है पंचायत के ऊपर कर्ज बढ़ गया है काग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है ये गोठान है।

चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान के तहत आज सुबह रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष जयंती पटेल, श्रीचंद सुंदरानी, नंदकुमार साहू, जितेंद्र धुरंदर मंडलआदि ने धनेली भटगांव, दतरेंगा व काँदुल गोठान का निरीक्षण कर गांव के लोगों से चर्चा की।गोठानों में हर जगह धांधली पाई गई। न तो गोठानों में गौ माता के दर्शन हुए, न गोबर दिखाई दिया, न ही चारे का इंतजाम नजर आया। गोबर खरीदी के नाम पर भारी हेराफेरी की शिकायत ग्रामीणों ने की। सांसद सुनील सोनी ने कहा घोटालों की सरकार के सरदार ने गौमाता को भी नहीं बख्शा। भूपेश सरकार द्वारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के नाम पर जो घोटाला हुआ है, वह हर गांव की जनता देख रही है। राजेश मूणत ने कहा भूपेश सरकार ने घोटालों में गौ मां को भी नही छोड़ा गौ मां को पीड़ित कर भूपेश सरकार ने अपराध किया है।धमतरी विधायक व भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने नगर निगम अंतर्गत ग्राम अर्जुनी गौठान की पोल खोलते हुए कहा कि भूपेश बघेल ढकोसला कर रहे हैं। न तो गोठान में गायें हैं और न ही चारा है न गोबर। सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। गोबर खरीदी के फर्जी आंकड़े बताते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने कोयला, रेत, शराब जैसे घोटालों से कहीं ज्यादा का गोबर घोटाला कर दिया है। विधायक श्रीमती रंजना साहू के साथ प्रदेश मंत्री रामू रोहरा, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा, कविंद्र जैन कार्यक्रम के विधान सभा संयोजक महेंद्र पंडित ने गोठान निरीक्षण किया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने राजिम के चौबेबान्धा बरौंडा में गोठान का निरीक्षण कर वहां की अव्यवस्था देखी। उन्होंने किसानों से बातचीत में सामने आई जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार गोधन और गोबर के नाम पर भारी भ्रष्टाचार तो कर ही रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

2000 के नोट बंद करने से नहीं मोदी सरकार बदलने से खत्म होगा भ्रष्टाचार-कांग्रेस

रायपुर। 2000 रु. के नोट को बंद करने के निर्णय को तुगलकी फरमान करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के दौरान ही कांग्रेस ने कहा था कि 2000 रु का नोट छापना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। भ्रष्टाचारियों को मदद करना है। 2000 रु. के नोट छापने और अभी बंद करने का निर्णय दोनों तुगलकी फरमान है जिसका खामियाजा आम जनता को ही भोगना पड़ेगा। मोदी सरकार के पास देश को चलाने के लिए ना तो कोई नीति है, ना ही इनकी कोई नियत है, बिना सोचे समझे बिना तैयारी के, की गई नोटबंदी से भ्रष्टाचारियों की कमर नहीं टूटी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। रोजी रोजगार के गंभीर संकट से देश आज भी जूझ रहा है। नगदी संकट अभी भी बना हुआ है, अब 2000 रु. का नोट बंद करने का निर्णय नोटबंदी से जख्मी हुए जनता के रोजी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय पर वज्र प्रहार है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार का 2000 रु के नोट बदलने से भ्रष्टाचार खत्म होने का दावा खोखला और दिखावटी है। जब करोड़ों का घोटाला करने वाले पर मोदी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती वो भ्रष्टाचारी भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं तब वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में नोटबंदी कर 2000 के नोटों को बंद करके मोदी सरकार का भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा खोखला है।

रमन सिंह और कितना झूठ बोलेंगे फोर्टिफाइड राइस को प्लास्टिक बता रहे: कांग्रेस

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा ट्वीट कर के राशन दुकानों में बांटे जाने वाले चावल को फोर्टिफाइड चावल को प्लास्टिक जैसी वस्तु बताया जाना बेहद ही आपत्तिजनक और निंदनीय। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डॉ. रमन सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिये स्तरहीन झूठा पोस्टर सोशल मीडिया में कर रहे है। फोर्टिफाइड चावल सूखे चावल को पीसकर आटा बनाकर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर पानी के साथ गूंथकर मशीनों की मदद से चावल के दानों के समान बनाया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2022 में निर्णय लिया था कि कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने के लिये राशन दुकानों और अन्य शासकीय योजनाओं में 100 फीसदी फोर्टिफाइड राइस बांटा जायेगा। यह चावल महिलाओं में खून की कमी को दूर करने में सहायक है। देशभर में यह चावल बांटा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता ह। चावल पर पोषक तत्वों की एक पर्त चढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा इसे पीसकर इनमें सूक्ष्म तत्वों को मिलाया जाता है ।

झीरम के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम बघेल: मूणत

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने झीरम हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ताजा बयान पर सवाल किया है कि झीरम मामले में मुख्यमंत्री बघेल के पास जो सबूत हैं, उसे वे सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आखिर वे सबूत कब तक सामने रखे जाएंगे? क्या कांग्रेस की प्रदेश सरकार झीरम मामले के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है? भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि झीरम मामले में मुख्यमंत्री बघेल जनता को गुमराह कर रहे हैं। झीरम घाटी में शहीद छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे थे। वे किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर पूरे प्रदेश के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री बघेल के पास जो भी सबूत और दस्तावेज इस मामले के हैं, उसे सार्वजनिक करें। श्री मूणत ने कहा कि यह मुख्यमंत्री बघेल के संज्ञान में होना चाहिए कि जिस समय इस हमले की जांच की घोषणा की गई थी, उस समय केन्द्र में कांग्रेसनीत संप्रग की सरकार थी। उस समय सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने रायपुर में एक बैठक में यह निर्णय करने के बाद इसकी जाँच की घोषणा की थी। भाजपा लगातार जाँच की मांग करती रही है। मुख्यमंत्री बघेल से सबूत व दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा जा रहा है, जिसके बारे में तत्कालीन कांग्रेस

भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस की सफलता की झांकी है : मोहन मरकाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भरोसे का सम्मेलन कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की सफलता की झांकी है। साढ़े चार साल पहले कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से वायदा किया था उसको तो पूरा किया ही उसके अलावा राज्य की जनता के भलाई के लिये कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाये जिससे राज्य के हर वर्ग के जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन आया। भरोसे का सम्मेलन उसी की जीवंत झांकी है जिसमें हितग्राही कांग्रेस पर कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जताते है। कांग्रेस राज के साढ़े चार साल में लोगो को भरोसा कांग्रेस के प्रति और बढ़ा है। यही कारण है कि 2018 का विधानसभा चुनाव दो तिहाई से जीतने के बाद कांग्रेस ने लगातार पांच उपचुनाव नगरी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में प्रचंड बहुमत से जनता का भरोसा जीता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के न्याय की बयार बह रही है। कांग्रेस सरकार युवाओं, किसानों मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति सभी के साथ न्याय कर रही राज्य की न्याय योजनाये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंजीकृत भूमिहीन परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है, योजना के माध्यम से मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

2 हजार का नोट बंद होने से कांग्रेस को गहरा धक्का क्यों लगा: बृजमोहन

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले के बाद कांग्रेस के बयानों से यह साफ है कि कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जब-जब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 2000 रुपए के नोट जमा कराने के लिए अभी 127 दिनों का पर्याप्त समय है, बावजूद इसके, कांग्रेस नेता व्यर्थ हायतौबा मचा रहे हैं। इससे यह तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार और उसमें संलिप्त लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कालेधन के तौर पर बड़ी मात्रा में जमा इन नोटों के चलन से बाहर होने पर कांग्रेस को हो रही तकलीफ जनता को समझ आ रही है। श्री अग्रवाल ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, माफिया राज पर होने वाली कार्रवाई के विरोध में सबसे पहला बयान कांग्रेस का ही क्यों आता है? आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों करोड़ रुपए के चावल घोटाले, शराब घोटाले, कोयला घोटाले, गौठान घोटाले, रेत घोटाले, भर्ती घोटाले समेत जितने भी घोटाले प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल में किए हैं।

राजीव के सपने को साकार कर रहा है छत्तीसगढ़ : बघेल

- **मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया**

रायपुर। **मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने** भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 21 मई को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि देश के विकास और नवनिर्माण में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजीव जी ने युवा प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। उनकी नवोन्मेषी और दूरदर्शी युवा सोच के कारण भारत में सूचनाक्रांति आई जिसने देश को एक नई गति और दिशा दी। उनकी पहल के प्रभाव के रूप में आज हम ई-प्रशासन का वर्तमान स्वरूप और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता देख पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया की नींव राजीव जी के कार्यकाल में ही रख दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव जी ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाकर देश की नींव मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मतदान की आयु 21 से घटाकर कर 18 वर्ष में ही युवाओं को मत देने का अधिकार दिलाया। विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देकर उन्होंने देश में उद्योगों के लिए नए रास्ते खोले। वास्तव में राजीव जी आधुनिक भारत के स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने कहा कि राजीव जी का छत्तीसगढ से गहरा लगाव रहा। यहां की आदिवासी संस्कृति और निवासियों को उन्होंने करीब से देखा, जाना और उनके विकास के लिए काम किया। गरियाबंद जिले के आदिवासी अंचल कुल्हाड़ीघाट में 1985 का उनका संक्षिप्त प्रवास आज भी लोगों की यादों में बसा है। इसी समय उन्होंने धमतरी जिले के दुगली की यात्रा की, जिसे अब राजीव ग्राम के नाम से भी जाना जाता है।

श्री बघेल ने कहा कि राजीव जी ने समावेशी विकास का सपना देखा और उसके लिए अनेकों नीतियां बनाई। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी अन्त्योदय से लेकर उद्यमियों तक सबके विकास के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर वर्ष 2020 में 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' शुरू की गई। जिसके तहत प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को सीधे उनके खातों में प्रति एकड़ 9 हजार रूपए कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) अंतरित की जा रही है। इसी प्रकार खेती किसानी में कृषि मजदूर के रूप में काम करने वाले लोगों को राहत देने के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव जी आतंकवाद के आगे नहीं झुके।

हाई स्कूल 9वीं, 10वीं एवं हायर सेकेन्डरी 11वीं एवं 12वीं मुख्य परीक्षा में 98.34 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् (बोर्ड) द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का परिणाम घोषित किया। पूर्व मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा उत्तर मध्यमा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (हाई स्कूल कक्षा 9वीं, 10वीं तथा हायर सेकेन्डरी कक्षा 11वीं, एवं 12वीं) की मुख्य परीक्षा में विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 98.34 प्रतिशत रहा। शंखनाद वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ अतिथियों द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कहा कि वे निराश ना हो फिर से मेहनत से पढ़ाई करें, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार संस्कृत के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार शर्मा, राज्य गो सेवक आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुन्दर दास, सदस्य छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् डॉ. तोयनिधि वैष्णव, सचिव श्रीमती पूर्णिमा पाण्डेय, सहायक संचालक परीक्षा लक्ष्मण प्रसाद साहू, माशिमं की सदस्य श्रीमती निवेदिता चटर्जी सहित छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् की कर्मचारी, प्राच्य संस्कृत विद्यालयों के प्राचार्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.